डाक पंजीयन सं. जयपुर सिटी/101/2020-22

R.N.I. No. RAJHIN/2014/56746

मीडिया दृष्टिकोण

वर्ष : 09 > अंक : 38 > मूल्य: 10 रुपए >पृष्ठ : 08

हिलव्यू समाचार

सनकी इंसान समझदारी में शून्य हो जाता है।
-शालिनी श्रीवास्तव

website: www.hsnews.in

साप्ताहिक समाचार पत्र

जयपुर, मंगलवार, 21 मार्च 2023 से 27 मार्च 2023 तक

क्या सत्ता की सनक का परिणाम है 19 ज़िलों की घोषणा?

3 से 7 जिलों की सुगबुगाहट से अचानक 19 जिलों की बम ब्लास्ट घोषणा क्या नहीं है सियासी दांवपेच!

शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। महाभारत में शकुनि ने अपने जादुई पासे फैंक कर हस्तिनापुर यहाँ तक कि द्रोपदी को भी अपने भांजे दुर्योधन के लिए कब्जे में करवा लिया था ठीक उसी तरह गहलोत सरकार ने 19 नए जिलों के पासे फैंककर सियासी सनक का तगड़ा दांवपेच खेला है लेकिन न जनता द्रौपदी है न वे स्वयं दुर्योधन कि जनता को अपने वश में कर सके और एक बार फिर सत्ता की शक्तिशाली गद्दी पर आसीन हो जायें। आम जनता के ऊपर आने वाला 19 जिलों के गठन का भार आम जनता अच्छी तरह महसूस कर सकती है बशर्ते बुद्धिजीवी वर्ग इस सियासी दांवपेच का पुनरावलोकन करे।

मंत्री सुखराम वैश्नोई की सात दिन की माँग पर सांचौर जिला बनना? जोधपुर और जयपुर का जिला विभाजन होना अपने आप में सियासी सनक की दस्तक महसूस होती है। राजधानी जयपुर में दो-दो निगम होने का दर्द आम जनता आज भी झेल रही है। दोनों निगम हमेशा भूखे-नंगे रहते हैं। ख़ज़ाना खाली है कि रट लगाये रहते हैं स्वयं मुख्यमंत्री। फिर मुख्यमंत्री महोदय ये क्यों भूल गए कि 19 जिलों के गठन में ख़र्च भी 19 गुना ही आएगा।

निःसन्देह कुछ क्षेत्रों के क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर उनका जिला बनना आवश्यक था लेकिन रेवड़ी की तरह जिला बनाकर बांटना नादान निर्णय घोषित होगा।

19 क़स्बों-तहसीलों को जिला बनाना कोई मामूली निर्णय नहीं हुआ बल्कि आम जनता के साथ आँख मिचौली हुई है कि 'तुम मुझे वोट देना मैं तुम्हें जिला देता हूँ!'

इस नए बिगुल के साथ जिला अस्पताल, कोर्ट,पुलिस विभाग,जिलाधिकारी कार्यालय इसी के साथ बढ़ता स्टॉफ, व्यवस्थाएँ, जिला समीकरण बनाना-बैठाना क्या एक साथ जनता पर इसका भार नहीं बढ़ेगा?

रामलुभाया कमेटी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले ही अपनी रिपॉर्ट सौंप दी थी और जानकार सूत्रों के हवाले से यह भी निश्चित था कि 3 की जगह 7 जिले प्रस्तावित हैं लेकिन अचानक 19 जिलों का नगाड़ा बजना प्रश्नचिन्ह लगाता है घोषणा के इस शंखनाद पर। जल्द ही रामलुभाया कमेटी की सम्पूर्ण पत्रावली प्राप्त कर तथ्यों पर चर्चा की जाएगी कि क्या यह 19 जिले बनना जनहित में है या फिर यह एक तरफ़ा निर्णय आम जनता के हितों पर कुठाराघात है?

सियासी सफ़रनामे के 19 नए जिले

1.अनूपगढ़	14. नीमकाथाना
2. बालोतरा	15. फलोदी
3. ब्यावर	16. सलूंबर
4. डीडवाना	17. सांचौर
5. दूदू	18. शाहपुरा (भीलवाड़ा)
6. गंगापुर सिटी	19. डीग
7. जयपुर उत्तर	
8. जयपुर दक्षिण	
9. केकड़ी	
10. जोधपुर उत्तर	
11. जोधपुर दक्षिण	
12. कोटपूतली	
13. बहरोड़	

तीन नए संभाग

1. बांसवाड़ा
2. पाली
3. सीकर

ख़बर-बेख़बर

मालवीयनगर जोन नगर निगम ग्रेटर की मनमानी चरम पर

क्या बिल्डरों के पैसों ने बाँध दी है उपायुक्त महेश मान की आँखों पर पट्टी!

हिलव्यू समाचार

जयपुर। निगम से ज़िम्मेदार अधिकारी कर्मचारी नदारद ,नगर निगम ग्रेटर के मालवीय नगर जोन में अवैध निर्माण चरम पर हैं क्योंकि उपायुक्त महेशं मान मनमानी और अभिमान पर उतर आए हैं। बिल्डरों से अवैध निर्माणों के नाम पर मोटा पैसा वसूल कर महेश मान ने चुप्पी धारण कर ली है।उन्हें किसी को जवाब नहीं देना बस अपने मान-सम्मान के अलावा सबका अपमान करना है और मनमानी करनी है।

मानो राजस्थान सरकार के ये जवाई बन गए हैं। 34 वर्षों से लगातार राजधानी जयपुर में टिके उपायुक्त महेश मान अब अपने आपे से बाहर हो गए हैं। लगातार आम जन और मीडियाकर्मियों द्वारा अवैध निर्माणों की शिकायतें मिलने के बावजूद महेश मान कोई कार्यवाही नहीं कर रहे।

इस सम्बंध में लिखित शिक़ायत रजिस्टर्ड डाक द्वारा शालिनी श्रीवास्तव हिलव्यू समाचार संपादक द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव उषा शर्मा, महापौर सौम्या गुर्जर एवं ग्रेटर आयुक्त महेंद्र सोनी नगर निगम ग्रेटर, उपायुक्त महेश मान नगर मालवीय नगर जोन निगम ग्रेटर को भेजी गई। किंतु 4 मार्च को भेजी गयी डाक 6 मार्च को लौटा दी गयी क्योंकि कार्यालय होली के कारण बन्द मिला लेकिन खुर्द-बुर्द और इस तरह फटा हुआ कि इसे फाड़कर पढ़ लिया गया और पुनः लिफ़ाफ़े में रखकर वापस भेजा गया है । प्रेषक द्वारा पुनः वापस न लेने पर डाक वापस मालवीयनगर जोन भेजी गई मगर 09 मार्च को भी डाक नहीं ली गयी जबकि यह कार्य दिवस था। इस तरह 11 व 14 मार्च को डाक पुनः लौटा दी जाती रही मालवीयनगर नगर निगम ग्रेटर से। पोस्टमेन रिपोर्ट लिखता रहा कि कोई नहीं मिला। पोस्टमैन की रिपोर्ट अनुसार तो मालवीयनगर जोन बन्द था लेकिन प्रथम वापसी में डाक पूरी तरह से खुर्द-बुर्द मिली आख़िर सरकार के ये ज़िम्मेदार अफसर-कर्मचारी इस तरह की आपराधिक गतिविधि कैसे कर जाते हैं? क्या वजह है कि ऐसे अफसर पर कोई कार्यवाही नहीं होती? डाक विभाग से गये डाकिए की रिपोर्ट भी संदिग्ध रही क्या उसे कार्यालय में ताला मिला था 09 व 14 मार्च को या बिल्डरों के पैसों ने बाँध दी उपायुक्त महेश मान की आँखों पर पट्टी और महेश मान ने डाकिए को कर दिया गुमराह या बना लिया हमराह?

महेश मान उपायुक्त मालवीयनगर जोन, नगर निगम ग्रेटर,जयपुर

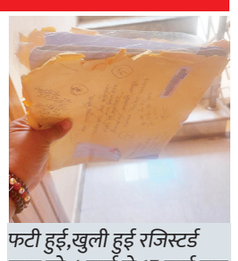

फटी हुई,खुली हुई रजिस्टर्ड डाक जो 4 मार्च से 17 मार्च तक वापसी आती रही मालवीयनगर नगर निगम ग्रेटर से। डाक विभाग या निगम ज़िम्मेदार?

राजस्थान सरकार जवाब दे-

- क्या मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर पर पड़ गया ताला?
- मालवीय नगर जोन उपायुक्त महेश मान की मनमानी क्यों है चरम पर?
- रजिस्टर्ड डाक 10-12 दिन से लगातार हो रही है वापस?
- क्या सरकारी कार्यालय कर सकते हैं ऐसा बचकाना व्यवहार?
- अवैध निर्माणों की सूचना व चर्चा से क्यों भागते हैं उपायुक्त महेश मान?

पत्रकार सुरक्षा क़ानून की माँग को लेकर पत्रकार संगठनों ने एकजुट होकर विधानसभा में किया घेराव

सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उपस्थित होकर दिया आश्वासन : जल्द लागू होगा पत्रकार सुरक्षा क़ानून

हिलव्यू समाचार

जयपुर। पत्रकारिता समाज का आईना होती है जो समाज और सरकार के बीच एक पुल का काम करती आ रही है। आपराधिक मामलों में स्पष्ट ख़बर प्रसारित करना,ग़लत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना,भूमाफियाओं के विरुद्ध बिगुल बजाना,सरकार की रीति,नीति कार्यशैली को लगातार जनता तक पहुँचाना, जनहित के मुद्दे उठाना,जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना, कर्त्तव्यों का अहसास करवाना ऐसे कई काम मीडिया के माध्यम से ही सम्भव है। ऐसे में मीडियाकर्मियों की सुरक्षा एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि क़लम की प्रखरता व तीखापन सीधे अपराधियों को कठघरे में खड़ा करता है। अतः पत्रकार सुरक्षा भी सरकार का दायित्व है। पिछले कई सालों में पत्रकारों पर हमले हुए हैं या कवरेज करते वक़्त कई पत्रकारों ने जीवन से हाथ धोया है। ऐसे में सरकार से सुरक्षा मिलने पर पत्रकारिता सुरक्षित रूप से समाज को नई दिशा व दशा दे सकती है।

इसी सोच के साथ पिंकसिटी प्रेस क्लब से,आईएफडब्ल्यूजे, भारतीय प्रेस आयोग, जार एसोसिएशन सहित कई पत्रकार सगठनों ने एक जुट होकर सरकार से पत्रकार सुरक्षा क़ानून की माँग की और चूंकि सरकारी घोषणापत्र में इस क़ानून की सरकार द्वारा घोषणा की गई थी उसे ही स्मरण करवाकर लागू करने का आव्हान 21 मार्च को पत्रकार संगठनों ने विधानसभा घेराव कर किया गया। सरकार की ओर से प्रतापसिंह खाचरियावास कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार के घोषणापत्र सरकारी होते हैं और उसमें पत्रकार सुरक्षा क़ानून अंकित किया जा चुका है जल्द ही सम्मान के साथ पत्रकारों को सुरक्षा क़ानून की सौगात भी दी जाएगी। इस आश्वासन से पत्रकारों में हर्ष है कि जल्द ही पत्रकार सुरक्षा क़ानून लागू होगा।

अब जयपुर की राजनीति में भी पनप रहा परिवारवाद

हेमलता अग्रवाल को राजस्थान सरकार के उपभोक्ता संरक्षण आयोग जयपुर - प्रथम में सदस्या बनाया जाना क्या नहीं है परिवारवाद का प्रतीक?

हिलव्यू समाचार

जयपुर। राजस्थान राज्य की कांग्रेस पार्टी लगातार सुर्ख़ियों में है। कभी सियासी संकट के बादल गरजते हैं तो कभी जनता की असंतुष्टि आंदोलन की आँधी बनकर सरकार को घेर लेती है। सत्ता की सनक राजस्थान सरकार को पागल किये दे रही है। घोषणाओं का बाज़ार गर्म है राजस्थान की राजनीति इस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है। ऐसे में भाई-भतीजावाद तो धीरे-धीरे जड़ें जमा ही रहा है कांग्रेस पार्टी में और अब राजधानी की राजनीति में परिवारवाद भी जड़ें पकड़ रहा है लेकिन अंदर की पुख़्ता ख़बर है कि यह कर्मठ कार्यकर्ताओं में असंतुष्टि फैला रहा है।

एक तरफ़ कांग्रेस द्वारा राज्य में हर स्तर पर लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है तो हेमलता अग्रवाल का सदस्य बनना लोकतंत्र पर कुठाराघात नहीं है कि एक बेटा आदर्शनगर विधानसभा में वार्ड 93 का पार्षद नीरज अग्रवाल है। दूसरा बेटा नितिन अग्रवाल कांग्रेस में लाभान्वित होकर दिल्ली में सोशल मीडिया प्रकोष्ठ में पदाधिकारी है और पति विमलेश अग्रवाल राजापार्क आदर्श नगर क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता का दबदबा बनाकर बिल्डर्स लाइजनर बने हुए हैं।

हेमलता अग्रवाल का राजस्थान सरकार के उपभोक्ता संरक्षण आयोग जयपुर - प्रथम में सदस्या बनना कार्यकर्ताओं में इसी कारण अविश्वास भर रहा है। दिन रात पार्टी के लिए खपने वाली महिला कार्यकताओं को मौक़ा न देकर अचानक हेमलता अग्रवाल का उपभोक्ता संरक्षण आयोग में सदस्य बनाया जाना परिवारवाद को बढ़ावा देकर पार्टी की जड़ें कमज़ोर करना ही है।

इनकमटैक्स विभाग व सरकारी ख़ज़ाने को चूना लगा रहे बिल्डर

मालवीय नगर निगम ग्रेटर सत्कार शॉपिंग सेंटर के पीछे सरकारी योजनाओं से मिले आवासीय भूखण्ड पर अवैध कमर्शियल शोरूम बनाकर करोड़ों में बेचने का खेल

निम्न आर्य वर्ग के स्थायी आवास के लिए सरकारी आवास योजनाएँ लायी जाती हैं लेकिन इसमें कुछ प्रोपेर्टी डीलर या बिल्डर्स इसे खरीद लेते हैं फिर खेल शुरू होता है सरकार से मिली कोड़ियों की ज़मीन को करोड़ों में बदलने का।

हिलव्यू समाचार

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड द्वारा निम्न आर्य वर्ग के स्थायी आवास के लिए सरकारी आवास योजनाएँ लायी जाती हैं लेकिन इसमें कुछ प्रोपेर्टी डीलर या बिल्डर्स इसे खरीद लेते हैं फिर खेल शुरू होता है सरकार से मिली कोड़ियों की ज़मीन को करोड़ों में बदलने का। सरकारी आवासीय योजनाओं के आवासीय भूखण्ड पर कमर्शियल बिल्डिंग,शोरूम कॉम्प्लेक्स खड़े किये जाते हैं और करोड़ों की क़ीमत में बेचे जाते हैं। इन सरकारी आवासों में अवैध निर्माणों के कारण बैंक लोन का कोई ऑप्शन नहीं होता। दो नंबर का मोटा पैसा देकर आने वाला ग्राहक इसे खरीदता है 70 % पैसा दो नंबर व 30% एक नंबर में रजिस्ट्री में शो किया जाता है यानि अपराध पर अपराध चलता है। भ्रष्टाचार की चैन बिल्डर्स से लेकर अधिकारियों, कर्मचारियों से होती हुई ग्राहक को बुरी तरह जकड़े होती है कि वह सिर्फ़ काम निकालने के भाव से प्रॉपर्टी क्रय करता है देशहित या लोकहित ग्राहक का विषय नहीं होता। सरकारी योजनाएँ धरातल पर नीलाम होती हैं साथ-साथ सरकारी रेवेन्यू को चूना लगता है कि आवसीय में कमर्शियल बिल्डिंग बन जाती हैं। इसके साथ इनकमटैक्स को जो चूना लगता है यह बहुत बड़ा मसला है। आख़िर सरकार की इन ग़रीब वर्ग की योजनाओं का कितना लाभ गरीब वर्ग को मिल पाता है यह सोचने का विषय है और इसके क्रियान्वयन में आवश्यक फेर-बदल की आवश्यकता है। करोड़ों में बिकने वाले ये शोरूम,कॉम्प्लेक्स या फ्लैट्स इनकमटैक्स की निग़ाह से क्यों ओझल है यह बड़े आश्चर्य की बात है।

लाइफ केयर हॉस्पिटल मालिक डॉ. तरुण पाटनी भी हैं अवैध निर्माणकर्ता

भूखण्ड संख्या 124,मोहन नगर,रिध्दि सिद्धि सर्कल के मुख्य मार्ग पर अवैध निर्माण कह रहा जेडीए के भ्रष्टाचार की कहानी

हिलव्यू समाचार

जयपुर। गोपालपुरा बायपास पर जेडीए के जोन 4 व 5 में पीआईएल लगी हुई है कि- अवैध निर्माणों को स्पेशल डवलपमेंट प्रोजेक्ट की आड़ में पालने के बजाए ध्वस्त करने की कार्यवाही हो।बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वाले बिल्डर्स और व्यापारियों पर अधिगम कोचिंग संस्थान की तरह ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हो न कि उन्हें आवासीय भूखण्डों पर गलियाँ निकालकर कमर्शियल पट्टे जारी किए जाएँ।

इसी श्रृंखला में बिल्डर्स ही नहीं समाज के नामी-गिरामी होटल,हॉस्पिटल के मालिक व प्रतिष्ठित लोग भी कर रहे हैं अवैध निर्माण।

आवासीय भूखण्ड संख्या 124 मोहन नगर,रिद्धि-सिद्धि सर्कल पर व्यवसायिक अवैध निर्माण लाइफ केयर हॉस्पिटल के मालिक डॉ तरुण पाटनी कर रहे हैं। जेडीए के जोन 5 में बिना अनुमति अवैध बहुमंज़िला कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है और जेडीए के अधिकारी कर्मचारी सब सो रहे हैं ? जेडीए की दोहरी दोगली नीति जनता में अविश्वास भर रही है।प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रण प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी इस विषय में निष्क्रिय हैं,मौन हैं क्यों?

आख़िर क्या वजह है कि गोपालपुरा बायपास रिद्धि सिद्धि सर्कल जयपुर पर लाइफ केयर हॉस्पिटल के मालिक डॉ तरुण पाटनी की अवैध बिल्डिंग प्लॉट न.124 पर कोई सीजर की कार्यवाही अब तक नहीं हुई है, कोई नोटिस अब तक जेडीए द्वारा इनको जारी नहीं किया गया। क्या वजह है कि जेडीए कई अवैध निर्माणों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। आम पीड़ित नागरिक या मीडिया द्वारा सूचित करने पर कोई हलचल जेडीए में देखने को नहीं मिलती। कोई कहने सुनने वाला नहीं। सरकार अपनी सत्ता बचाने में व्यस्त है और प्रशासन की जेबें गर्म हैं बस और क्या चाहिए। नियम, क़ानून, क़ायदे ताक में रखकर शासन और प्रशासन जनता का पैसा लूट रहे हैं और लुटा रहे हैं लेकिन बुराई का अंत निश्चित है और समय बड़ा बलवान। वक़्त पर हिसाब देना ही होगा हर भ्रष्टाचारी को।

राइट टू हेल्थ बिल लागू

क्या डॉक्टर्स के साथ कांग्रेस सरकार का रवैय्या ठीक था?

कुलदीप गुप्ता

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध करते निजी अस्पतालों के चिकित्सकों के साथ सरकार की सख़्ती कई प्रश्न खड़े करती है।

ईश्वर का प्रतिरूप कहे जाने वाले डॉक्टर्स पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया बेहद शर्मनाक और अफ़सोस जनक घटना है।

- लाठी चार्ज करवा कर वर्तमान सरकार कौनसी मज़बूरी का गीत गाना चाहती है ?
- धरना स्थल पर उपस्थित डॉक्टर्स कोई अपराधी थे ?
- क्या डॉक्टर्स ने किसी भी तरह की कोई आगजनी की ?

- क्या डॉक्टर्स ने आम जनता को परेशान किया ?
- क्या डॉक्टर्स ने पत्थरबाजी कर देश की सम्पति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की?

अगर नहीं तो गहलोत सरकार ने जिस दमनकारी नीति का प्रयोग करते हुए डॉक्टर्स के साथ पशुवत व्यवहार किया है वह भविष्य में बड़ा संकट लेकर आएगा।

राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 लागू

कुलदीप गुप्ता

जयपुर। लम्बे समय से चल रही वकीलों की सुरक्षा कानून की मांग अब पूरी हो गई है। विधानसभा में राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 पास हो गया।इस विधेयक का उद्देश्य अधिवक्ताओं के खिलाफ मारपीट, गंभीर चोट, आपराधिक बल और आपराधिक धमकी के अपराधों और अधिवक्ता की संपत्ति को नुकसान की रोकथाम के लिए है।

राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 का संक्षिप्त विवरण

- इस विधेयक का उद्देश्य अधिवक्ताओं के खिलाफ़ मारपीट, गंभीर चोट, आपराधिक बल और आपराधिक धमकी के अपराधों और अधिवक्ता की संपत्ति को नुकसान या नुकसान की रोकथाम के लिए प्रदान करना है।
- विधेयक की धारा 3 न्यायालय परिसर में अधिवक्ता के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में अधिवक्ताओं पर हमला, गंभीर चोट, आपराधिक बल और आपराधिक धमकी को निषेध करती है।
- धारा 4 (Advocate Protection Bill) में प्रावधान है कि एक वकील द्वारा उसके ख़िलाफ़ किए गए अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित किसी अपराध के संबंध में पुलिस को दी गई किसी भी रिपोर्ट पर, पुलिस, यदि उचित समझे, तो उसे निर्धारित अवधि के लिए और इस तरह से सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

दखल

वन्यजीवों के अस्तित्व पर संकट

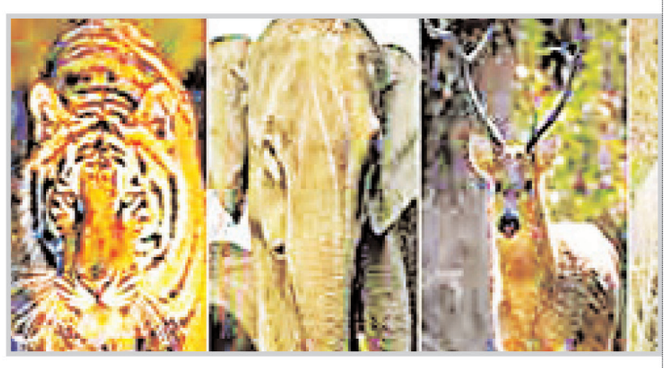

शोधकर्ताओं का मानना है कि समुद्री जैव विविधता पर लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है और मछली पकड़ने का दबाव, भूमि तथा महासागर में अम्लीकरण का बढ़ना आदि ऐसे कारण हैं, जिनसे समुद्री जीवों पर विलुप्ति का संकट मंडरा रहा है। जंगलों में अतिक्रमण, कटान, बढ़ते प्रदूषण तथा पर्यटन के नाम पर गैरजरूरी गतिविधियों के कारण पूरी दुनिया में जैव विविधता पर संकट मंडरा रहा है। यह पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का साफ संकेत है।

विश्व वन्यजीव कोष की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 में खुलासा हुआ है कि दुनिया भर में पिछले 50 वर्षों में वन्यजीवों की आबादी 69 फीसद कम हुई है। इनमें स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, सरीसृप, मछलियां आदि शामिल हैं। हर दो साल में प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो पूरी दुनिया में वन्यजीवों की आबादी तेजी से घट रही है, लेकिन 1970 के बाद से लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियाई क्षेत्रों में वन्यजीव आबादी में करीब 49 फीसद तक की गिरावट आई है, जबकि अफ्रीका में 66 और एशिया में 55 फीसद गिरावट हुई है। मछली पकड़ने में 18 गुना वृद्धि होने के कारण शार्क तथा 'रे' मछलियों की संख्या में 71 फीसद कमी हुई है, जबकि ताजा पानी में रहने वाली प्रजातियों में सर्वाधिक 83 फीसद की गिरावट दर्ज हुई है, जो किसी भी प्रजाति समूह की तुलना में बड़ी गिरावट है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि वनों की कटाई, आक्रामक नस्लों का उभार, प्रदूषण, जलवायु संकट तथा विभिन्न बीमारियां इसका मुख्य कारण हैं। डब्लूडब्लूएफ के महानिदेशक मार्को लैंबर्टिनी के अनुसार हम मानव-प्रेरित जलवायु संकट व जैव विविधता के नुकसान की दोहरी आपात स्थिति का सामना कर रहे हैं, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए खतरा साबित हो सकती है। दरअसल, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, उद्योगीकीकरण, शहरीकरण, शिकार, वृक्षों की कटाई आदि कार्यों से धरती में बड़े बदलाव हो रहे हैं। प्रदूषण वातावरण और प्रकृति के बदलते मिजाज के कारण दुनिया भर में जीव-जंतुओं व वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। वनस्पतियां तथा जंतुओं की तमाम प्रजातियां मिलकर ही आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं और वन्य जीव चूंकि हमारे मित्र भी हैं, इसलिए उनका संरक्षण किया जाना बेहद जरूरी है।

इससे पहले आईयूसीएन (इंटरनेशनल यूनियन फार कन्जर्वेशन आफ नेचर) की 2021 की रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि दुनिया भर में वन्यजीवों तथा वनस्पतियों की हजारों प्रजातियां संकट में हैं और आने वाले समय में इनके धरती से गायब होने की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। आइयूसीएन ने विश्व भर में करीब 1.35 लाख प्रजातियों का आकलन करने के बाद इनमें से 37,400 प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर मानकर 'लाल सूची' में शामिल किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक 900 जैव प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और 37 हजार से ज्यादा पर विलुप्त होने का संकट मंडरा रहा है। अगर जैव विविधता पर संकट इसी प्रकार मंडराता रहा, तो विश्वभर में दस लाख से अधिक प्रजातियां खतरे की श्रेणी में या विलुप्ति के कगार पर होंगी। दुनिया के सबसे वजनदार पक्षी 'एलिफेंट बर्ड' का अस्तित्व अब धरती से खत्म हो चुका है। इसी प्रकार एशिया और यूरोप में मिलने वाले रोएंदार गैंडे की प्रजाति भी अब इतिहास बन चुकी है।

समुद्र में 70 वर्ष तक का जीवन चक्र पूरा करने वाला डूगोंग प्रजाति का 'स्टेलर समुद्री गाय' नामक जीव भी विलुप्त हो चुका है। अब कुछ खास प्रजाति के पौधों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। एक अन्य शोध में यह चौंकाने वाला तथ्य आया है कि 97 फीसद धरती की पारिस्थितिकी सेहत बेहद खराब हो चुकी है और मानवीय हस्तक्षेप से दूर रहने के कारण तथा वहां के स्थानीय जनजातीय लोगों की भूमिका से तीन फीसद हिस्सा ही पारिस्थितिकी रूप से सुरक्षित रह गया है। 'फ्रंटियर्स इन फारेस्ट एंड ग्लोबल चेंज' नामक एक पर्यावरण विज्ञान जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं का कहना है कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण पृथ्वी के जैव विविधता वाले क्षेत्रों में इतनी तबाही मच चुकी है कि धरती का केवल तीन फीसद हिस्सा इससे पूरी तरह बचा रह पाया है। ब्रिटेन स्थित स्मिथसोनियन एनवायरनमेंटल रिसर्च सेंटर के शोधकर्ता किंबली कोमात्सू के मुताबिक विश्व के केवल 2.7 फीसद हिस्से में अप्रभावित जैव विविधता बची है, जो बिल्कुल वैसी ही है, जैसी पांच सौ वर्ष पूर्व हुआ करती थी।

शोधकर्ताओं के अनुसार अप्रभावित जैव विविधता वाला क्षेत्र जिन जिन देशों की सीमाओं के अंतर्गत आता है, उनमें से केवल 11 फीसद क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है और संबंधित सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। अप्रभावित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से अधिकांश उत्तरी गोलार्ध में हैं, जहां मानव उपस्थिति कम रही है, पर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ये जैव विविधता से समृद्ध नहीं थे। धरती पर वन्यजीवों के अस्तित्व पर मंडराते संकट को लेकर शोधकर्ताओं का कहना है कि अधिकांश प्रजातियां मानव शिकार के कारण लुप्त हुई हैं, जबकि कुछ अन्य कारणों में दूसरे जानवरों का हमला तथा बीमारियां शामिल हैं। हालांकि कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर शोधकर्ताओं का मानना है कि धरती के ऐसे 20 फीसद हिस्से की जैव विविधता को बचाया जा सकता है, जहां अभी पांच या उससे कम बड़े जानवर ही गायब हुए हैं, लेकिन इसके लिए मानव प्रभाव से अछूते क्षेत्रों में कुछ प्रजातियों की बसावट बढ़ानी होगी, जिससे पारिस्थितिक तंत्र को लाभ होगा। जलवायु परिवर्तन से हाल के समय में विलुप्त हुई प्रजातियों, उनके इधर-उधर जाने, पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रजातियों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद अमेरिका की यूनिवर्सिटी आफ एरिजोना के शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि अगले 50 वर्षों में पौधों तथा जानवरों की एक तिहाई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी।

शोधकर्ताओं ने दुनिया भर के 581 स्थानों से 538 प्रजातियों पर निरंतर दस वर्षों तक अध्ययन करने के बाद पाया कि अधिकांश स्थानों पर 538 प्रजातियों में से 44 फीसद प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इस अध्ययन में विभिन्न मौसमी कारकों का अध्ययन करने के बाद शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही तो 2070 तक दुनिया भर में कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वन्यजीवों की तस्करी दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुनिया भर में सर्वाधिक तस्करी स्तनधारी जीवों की होती है, उसके बाद रेंगने वाले जीवों की 21.3, पक्षियों की 8.5 तथा पेड़-पौधों की 14.3 फीसद तस्करी होती है। समुद्री प्रजातियों पर मानव प्रभावों का मूल्यांकन करने वाले एक शोध में पता चला है कि इंसानी गतिविधियों के कारण करीब 57 फीसद समुद्री प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं।

आईयूसीएन की 'लाल सूची' की 1271 खतरे वाली समुद्री प्रजातियों के आंकड़ों के आधार पर शोधकर्ताओं ने 2003 से 2013 तक मानवीय गतिविधियों से खतरे में आई प्रजातियों के आकलन के जरिए यह निष्कर्ष निकाला। शोधकर्ताओं का मानना है कि समुद्री जैव विविधता पर लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है व मछली पकड़ने का दबाव, भूमि व महासागर में अम्लीकरण का बढ़ना ऐसे कारण हैं, जिनसे समुद्री जीवों पर विलुप्ति का संकट मंडरा रहा है। जंगलों में अतिक्रमण, कटान, बढ़ते प्रदूषण तथा पर्यटन के नाम पर गैरजरूरी गतिविधियों के कारण दुनिया में जैव विविधता पर संकट मंडरा रहा है। यह पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का संकेत है और अगर इसमें सुधार के शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैव विविधता के क्षरण का सीधा असर भविष्य में पैदावार, खाद्य उत्पादन आदि पर पड़ेगा, जिससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह से प्रभावित होगा।

योगेश कुमार गोयल
(वरिष्ठ पत्रकार)

सम्पादकीय

बाल विवाह पर रोक ज़रूरी

बाल विवाह, समाज की जड़ों तक फैली बुराई, लैंगिक असमानता और भेदभाव का ज्वलंत उदाहरण है। यह आर्थिक और सामाजिक ताकतों की क्रिया-प्रतिक्रिया का परिणाम है। इस लिहाज से तो असम सरकार की कार्रवाई सही है और उस पर सवाल उठाना गलत है।

असम में बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार की मुहिम को सांप्रदायिक रंग देकर देशभर में माहौल खराब करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल, असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ सख्त ऐक्शन ले रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि बाल विवाह पर किसी तरह की सांप्रदायिक कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरमा ने यहां तक कह दिया- आपके पास दो विकल्प है, या तो मुझे यहां से हटा दो या बाल विवाह बंद करो, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अपराधियों को हर छह महीने में गिरफ्तार किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को पकड़ा गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि राज्य में एक वर्ग पर संकट है। जबकि सरकार का कहना है कि राज्य में तीन फरवरी की कार्रवाई के बाद से मुसलमानों और हिंदुओं की गिरफ्तारी का अनुपात 55 :45 है। इस लिहाज से किसी एक वर्ग पर कार्रवाई करना गलत है।

कुछ भी हो, असम सरकार और वहां के लोगों के तर्क कुछ भी हों, मगर बाल विवाह एक तरह से गलत है। इस पर रोक के लिए कितनी भी बड़ी कार्रवाई की जाए, वह सही है। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है जिससे उन पर हिंसा, शोषण व यौन शोषण का खतरा बना रहता है। बाल विवाह लड़कियों और लड़कों दोनों पर असर डालता है, लेकिन इसका प्रभाव लड़कियों पर अधिक पड़ता है। किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह में औपचारिक विवाह तथा अनौपचारिक संबंध भी आते हैं, जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे शादीशुदा जोड़े की तरह रहते हैं। बाल विवाह, बचपन खत्म कर देता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़कियों पर, बल्कि उनके परिवार और समुदाय पर भी होता हैं।

जिस लड़की की शादी कम उम्र में हो जाती है, उसके स्कूल से निकल जाने की संभावना बढ़ जाती है तथा उसके कमाने व समुदाय में योगदान देने की क्षमता कम हो जाती है। उसे घरेलू हिंसा तथा एचआईवी/एड्स का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। खुद नाबालिग होते हुए भी उसकी बच्चे पैदा करने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान गंभीर समस्याओं के कारण अक्सर नाबालिग लड़कियों की मृत्यु भी हो जाती हैं। अनुमानित तौर पर भारत में प्रत्येक वर्ष, 18 साल से कम उम्र में करीब 15 लाख लड़कियों की शादी होती है जिसके कारण भारत में दुनिया की सबसे अधिक बाल वधुओं की संख्या है, जो विश्व की कुल संख्या का तीसरा भाग है। 15 से 19 साल की उम्र की 16 प्रतिशत लड़कियां शादीशुदा हैं। 2005-2006 से 2015-2016 के दौरान 18 साल से पहले शादी करने वाली लड़कियों की संख्या 47 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत रह गई है, पर यह अभी भी अत्याधिक है।

विकास के बजाय उपहार का सहारा

जनता को मुफ्त सुविधाएं बांटने के फेर में केंद्र और राज्य सरकारें कर्ज के बोझ तले दबती जा रही हैं। वित्तवर्ष 2022-23 में केंद्र ने 4.36 लाख करोड़ की सब्सिडी बांटी है। आगामी वित्तवर्ष 2023-24 में केंद्र ने सब्सिडी को कम जरूर किया है, लेकिन कोरोना काल से जारी मुफ्त राशन योजना को दिसंबर 2023 तक विस्तार दे दिया है। राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना के अंतर्गत देश भर में मुफ्त अनाज लेने वाले लाभर्थियों की संख्या करीब 90 करोड़ है। केंद्रीय मंत्री संसद में स्वीकार कर चुके हैं कि राज्यों में फर्जी राशन कार्डों के माध्यम से 55.37 लाख अपात्र लाभार्थी योजना का लाभ ले रहे हैं। वित्तवर्ष 2022-23 में सरकार ने मनरेगा पर 90 हजार करोड़ रुपए खर्च किए। बदले में 25 फीसद विकास कार्य भी देश में नहीं दिखाई दिए हैं।

रिजर्व बैंक का आकलन है कि बीते वर्ष में राजस्व में एक फीसद की अवश्य वृद्धि हुई है, लेकिन केंद्रीय बजट में सब्सिडी का हिस्सा सात फीसद तक पहुंच गया है। यानी सरकार जीएसटी और अन्य करों के माध्यम से वसूली कर रही है, तो उससे कई गुना राशि मुफ्त में बांट रही है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों में चुनाव जीतने के लिए मुफ्त रेवड़ी की घोषणा एक सुलभ उपाय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। इससे देश का बुनियादी ढांचा चरमरा गया है। अब देश के आम आदमी की मानसिकता गरीब बनकर जीवन यापन की हो चुकी है। वह अपने स्तर से ऊपर आना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे मिलने वाली मुफ्त और अनुदान आधारित योजनाओं के छिन जाने का डर है! देश के दस राज्य अपनी कर्ज लेने की अंतिम सीमा रेखा पार कर चुके हैं।

आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि इन राज्यों ने मुफ्त बांटने की योजनाओं पर रोक नहीं लगाई, तो राज्यों में विकास की स्थिति श्रीलंका व पाकिस्तान जैसी होगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के तीस राज्यों ने अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक नौ माह की अवधि में 2.28 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जबकि अगले तीन माह जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक 3.34 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने की कतार में शामिल थे। आरबीआई की रिपोर्ट में घोषित दस राज्यों- पंजाब, केरल, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, मध्यप्रदेश के हालात यह हैं कि इनकी समस्त आय का 90 फीसद हिस्सा सिर्फ कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन, ब्याज, सब्सिडी पर खर्च हो रहा है। सभी व्यय के बाद इन राज्यों में विकास के लिए दस फीसद हिस्सा भी नहीं बच रहा है। सवाल यह भी है कि क्या ये राज्य लिए गए कर्ज कभी लौटा पाएंगे? स्थितियां बदतर हैं, लेकिन चुनावी प्रबंधन के लिए मुफ्त घोषणाओं में कोई भी सरकार पीछे नहीं है।

राज्यों की मुफ्त घोषणाओं ने सबसे अधिक नगरीय विकास को प्रभावित किया है। संस्थाओं में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती के बजाय ठेके पर काम लिया जा रहा है। इसके चलते नागरिक सेवाओं में गुणवत्ता और उत्तरदायित्वों का अभाव होने लगा है। नागरिक सेवाओं की बेहतर बहाली के बजाय सरकारें सिर्फ वोट प्रबंधन कर सत्ता हासिल करने में जुट गई हैं। जबकि यह देश के वित्तीय ढांचे के लिए बेहद नुकसानदेह है।

रिजर्व बैंक की गणना के अनुसार सरकार के वित्तीय अनुशासन में कर्ज का बोझ उस राज्य की जीडीपी के तीस फीसद से अधिक नहीं होना चहिए, लेकिन पंजाब 53.3 फीसद, राजस्थान 40 फीसद, बिहार 38, उत्तर प्रदेश 34, मध्यप्रदेश 32 फीसद का बोझ लिए बैठे हैं। इन राज्यों को और अधिक कर्ज देने से वित्तीय संस्थाएं परहेज कर रही हैं, लेकिन जरूरतमंद राज्य अचल संपतियां व प्रतिभूति गिरवी रख कर भी कर्ज मांगने की कतार में शामिल हैं। इन राज्यों में जो नागरिक नियमित कर अदा कर रहा है, उस पर और अधिक कर, विकास अधिभार लाद कर राज्य आय के संसाधन विकसित कर रहे हैं। इनकी स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी अति आवश्यक सुविधाएं पिछड़ चुकी हैं। आवश्यक सेवाओं में भी नियमित भर्ती के स्थान पर संविदा और अतिथि कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं। अर्थशास्त्री मानते हैं कि अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़ कर उन योजनाओं पर, जिनका प्रतिदान शून्य हो, राज्य की जीडीपी हिस्सेदारी एक फीसद से अधिक की नहीं होनी चहिए। मगर मुफ्त और अनुदान आधारित योजनाओं में पंजाब राज्य की 2.7, आंध्र प्रदेश 2.1, मध्यप्रदेश 1.5 और राजस्थान की 2.0 फीसद हिस्सेदारी है।

पंजाब की आबादी करीब तीन करोड़ है और उस पर कर्ज तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। इस तरह राज्य के प्रत्येक नागरिक पर एक लाख का कर्जा है। राज्य के 25 फीसद युवा बेरोजगार हैं। राज्य सरकार रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पा रही है। अमूमन यह स्थति उन सभी राज्यों की है, जिन्हें आरबीआई ने संवेदनशील राज्यों की श्रेणी में रखा है। विश्व बैंक का आकलन है कि देश के नगर निकायों को स्थानीय विकास, जल निकासी और जल प्रदाय के लिए 15 वर्षों में 840 अरब डालर की दरकार है। नगर निकाय अभी तक केंद्र व राज्य सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भर रहते आए हैं। राजनीतिक कुप्रबंधन के कारण निकाय अपने आय के स्रोत विकसित करने में विफल रहे हैं। कर्ज में डूबे राज्यों की मुफ्त घोषणाओं ने सबसे अधिक नगरीय विकास को प्रभावित किया है।

संस्थाओं में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती के बजाय ठेके से काम लिया जा रहा है। इसके चलते नागरिक सेवाओं में गुणवत्ता और उत्तरदायित्वों का अभाव होने लगा है। नागरिक सेवाओं की बेहतर बहाली के बजाय, सरकारें सिर्फ वोट प्रबंधन कर सत्ता हासिल करने में जुट गई हैं। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रति वर्ष देश के किसानों को साठ हजार करोड़ रुपए तक की राशि केंद्र सरकार देती है। कई राज्य सरकारें इसके अलावा भी आवंटन कर रही हैं। मगर देश में कृषि क्षेत्र की हालत यह है कि अगर प्रकृति तनिक भी विचलित हो जाए तो किसानों के पास अगले दिन की व्यवस्था नहीं है। सवाल है कि हम किसानों को योजनाओं के माध्यम से कितना सक्षम बना पाए हैं? आज देश के प्रत्येक किसान परिवार पर औसतन 74,121 रुपए का कर्ज है। जबकि प्रति परिवार मासिक आय मात्र 10,218 रुपए है।

अर्थशास्त्रियों की चेतावनी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर अनुदान के बजाय सारी मुफ्त योजनाएं देश को गर्त में उतारने के लिए है। तीन बड़े हिंदी राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आरबीआई की सूची में मध्यप्रदेश और राजस्थान कर्ज सीमा लांघ कर संवेदनशील इलाके में पहुंच चुके हैं। इन राज्यों को अपने कर्मचारियों के मासिक वेतन और पेंशन के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। मप्र सरकार का दावा है कि वह जन्म के पूर्व से लेकर अंत्येष्टि तक गरीबों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। अब राज्य सरकार ने प्रदेश की 2.50 लाख से कम आय वाली प्रत्येक महिला को एक हजार रुपए मासिक पेंशन देने का फैसला किया है। इस लाडली बहना योजना पर सरकार पांच साल में करीब 61 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि वित्तवर्ष 2023-24 में राज्यों में कर संग्रह पिछले साल की अपेक्षा दो फीसद कम रहेगा। आगामी वर्षों में अब राज्यों को केंद्र की बैसाखी छोड़ आय के स्रोत विकसित करना होगा। मगर मुफ्त बांट कर सत्ता प्राप्ति का सूत्र राज्यों को दिवालिया व नागरिकों को आश्रित बना रहा है। इस स्थिति से जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सरकारों को रेवड़ी कल्चर से दूर रहने को कह चुके हैं। फिर भी कुछ सरकारें जनता को बांटने से गुरेज नहीं कर रही हैं और संकट बढ़ा रही हैं।

विनोद के शाह
(वरिष्ठ पत्रकार)

राज्य में बाल विवाह स्वीकार्य नहीं हैं। कुछ लोग अपराधियों के लिए रो रहे हैं, पर पीड़ित परिवार के उन बच्चियों के लिए नहीं जो 11 साल की उम्र में गर्भवती हो जाती हैं।

हिमंत बिस्वा सरमा, मुख्यमंत्री

जिन समुदायों में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है वहां उन समुदायों की सामाजिक प्रथा और दृष्टिकोण का हिस्सा है तथा यह लड़कियों के अधिकारों की निम्न दशा दर्शाता है।

योगेंद्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता

सत्यार्थ

भूख और ईश्वर का संकेत

एक समय की बात है, तीन साधु ज्ञान की खोज में हिमालय पहुंचे। पहाड़ी गांवों से गुजरते हुए लोगों से जो कुछ मिलता खा लेते और अपनी खोज में चलते रहते। एक दिन उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने पाया कि उनके पास रोटियां सिर्फ दो बची थीं। उन्होंने तय किया कि उस दिन वे भूखे ही सो जाएंगे। सपने में आकर ईश्वर जिसे रोटी खाने का संकेत देंगे, वही रोटियां खाएगा। ऐसा फैसला कर तीनों साधु सो गए। आधी रात के बाद अचानक तीनों साधु उठे और उठकर एक दूसरे को अपना सपना सुनाने लगे। पहले ने कहा, 'मैं सपने एक निर्जन किंतु दिव्य स्थल पर पहुंचा। वहां अपार शांति थी और वहीं मुझे ईश्वर के दर्शन हुए। ईश्वर ने मुझसे कहा तुमने जीवन भर दूसरों के लिए त्याग किए हैं, इसलिए ये रोटियां तुम्हें खानी चाहिए'। दूसरे साधु ने भी अपना सपना सुनाया। उसने कहा, 'मैंने देखा अपने पिछले जन्म की तपस्या के कारण मैं महात्मा बन गया हूं। अचानक ईश्वर मेरे सामने प्रकट हुए और बोले- कठिन तपस्या करते हुए तुम औरों से श्रेष्ठ हो गए हो। तुम्हारे पास पुण्य का अथाह भंडार संचित हो गया है, इसलिए इस पुण्य की बदौलत रोटियों पर पहला हक तुम्हारा बनता है।' तीसरा साधु अपने दोनों मित्रों की बात बड़े शांत भाव से सुन रहा था। अब उसके बारी थी। उसने बड़ी शांति और गंभीरता से कहा, 'मुझे सपने में ईश्वर नहीं मिले। न ही उन्होंने मुझे रोटियां खाने को कहा। आधी रात को अचानक भूख से मेरी नींद खुली और मैंने रोटियां खा लीं।' दोनों साधु चिल्लाए-'अरे, तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया?' 'कैसे बताता, तुम दोनों तो गहरी नींद में ईश्वर से साक्षात्कार करने में लगे हुए थे। मुझे ईश्वर ने तीव्र भूख का अनुभव कराया और मेरी नींद खुलवा दी। यही संकेत मेरे लिए पर्याप्त था कि मुझे रोटियां खा लेनी चाहिए!

आरडी गर्ग

वादे निभा रही गहलोत सरकार: विधानसभा में दो महत्वपूर्ण बिल आए: एक पास...एक फेल

वकीलों को मिलेगी पुलिस सुरक्षा, मारपीट पर 7 साल तक की सज़ा

हिलव्यू समाचार

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को दो महत्वपूर्ण कानून बनाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने वकीलों को सुरक्षा देने के बनाए जाने वाले नए कानून का विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। सरकार ने वकील संगठनों के साथ हुए समझौते में 15 मार्च को यह विधेयक विधानसभा में रखने और 21 मार्च को पारित करने का वादा किया था। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के आम नागरिकों को राइट-टू-हेल्थ देने के बिल पर विधानसभा की सलेक्ट कमेटी ने मुहर लगा दी है। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक को विधि मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में रखा। इसका वकीलों की तरफ से स्वागत किया गया है। वकीलों की सुरक्षा के लिए पेश किए गए बिल में सुरक्षा और सजा दोनों के प्रावधान रखे गए हैं। बिल में प्रावधान है कि यदि वकील की तरफ से विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा की मांग की जाती है तो पुलिस को उपलब्ध करवानी होगी। वहीं, वकील के कोर्ट परिसर में रहने के दौरान या उसके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कोई हमला करता है तो उसके लिए 7 साल तक की सजा और पचास हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में वकील को धमकी देने की स्थिति में दो साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अधिवक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या आग लगाने का कोई अपराध करता है तो उस स्थिति में दोषी व्यक्ति को सात साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है।

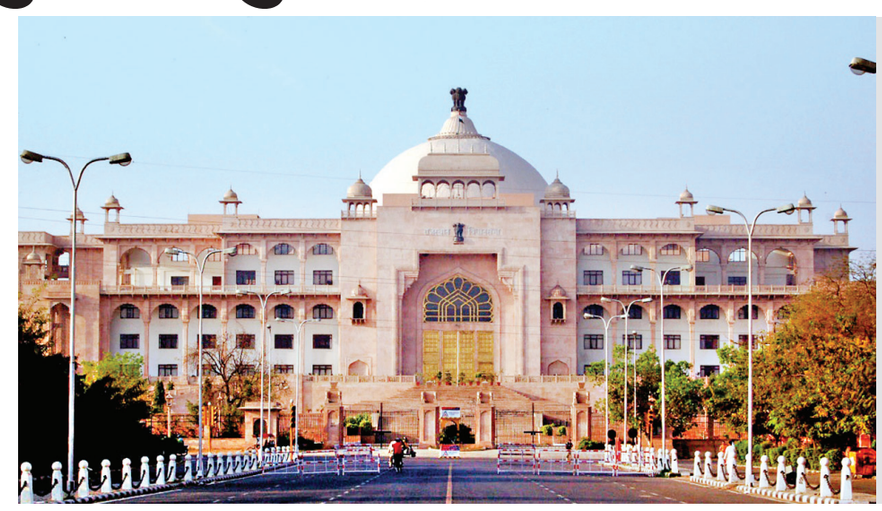

अधिवक्ता के ख़िलाफ़ मिली शिक़ायत का निस्तारण 7 दिन में करना ज़रूरी

विधेयक में प्रावधान किया गया है कि अधिवक्ता को लेकर उसका मुवक्किल या विरोधी मुवक्किल की तरफ से पुलिस में शिकायत दी जाती है तो उसकी जांच सात दिन में पूरी की जाएगी। साथ ही ऐसे मामले की जांच उप-अधीक्षक से नीचे की रैंक का नहीं होगा।

राइट टू हेल्थ बिल के विरोध पर हो गए थे दो फाड़

■ राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी संगठन आमने-सामने हो गए थे। बिल के विरोध में प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी ने ऐलान कर दिया था कि गुरुवार को प्रदेशभर में अस्पताल बंद नहीं होंगे।

■ जॉइंट एक्शन कमेटी ने इस बंद को समर्थन देने से इनकार कर दिया था। कमेटी मीडिया प्रभारी डॉ. संजीव गुप्ता ने स्पष्ट किया था कि चेयरमैन सुनील चुग की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में निर्णय लिया गया कि कमेटी की मांगों को मानते हुए सरकार ने बिल की सभी विसंगतियो को दूर किया है। ऐसे में बंद करने का कोई औचित्य नहीं रह गया।

एक नज़र

प्रशासन शहरों के संग में 7.71 लाख से ज्यादा पट्टे किए जारी

हिलव्यू समाचार

जयपुर। स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 421 परियोजनाओं में से 345 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 46 प्रगतिरत हैं। इस योजना में राजस्थान ने पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत 4 वर्ष में 29 शहरों में सीवरेज, जलप्रदाय आदि के लिए 1945 करोड़ व्यय किए गए। अमृत 2.0 के अंतर्गत 26 शहरों में सीवरेज की 3528 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई। धारीवाल बुधवार को विधानसभा में स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने स्वायत्त शासन विभाग की 103 अरब 72 करोड़ 84 लाख 38 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी। धारीवाल ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में 7 लाख 71 हजार से अधिक पट्टे जारी किए जा चुके हैं। भवन मानचित्र, नाम हस्तांतरणलीज आदि के 18 लाख 18 हजार आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।

बेरोजगारों को 50 हजार तक का ऋण

स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत अब तक 10.59 करोड़ भोजन थालियां परोसी गई हैं। योजना के अंतर्गत जरुरतमंदों को 8 रुपए में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन सम्मानपूर्वक बैठाकर दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 17 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में स्ट्रीट वेण्डर्स एवं बेरोजगारों को रोजगार के लिए 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक 1 लाख 82 हजार 123 लाभार्थियों को 480.96 करोड़ राशि का ऋण वितरित किया जा चुका है। धारीवाल ने कहा कि राजस्थान आवासन मंडल आज सफलता की नई इबारतें लिख रहा है। उन्होंने बताया कि मंडल का टर्न ओवर 7500 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है।

शाखावार सामाजिक सर्वेक्षण करेगा संघ

समाधान की दिशा में काम करेंगे स्वयंसेवक

■ युवाओं में RSS को लेकर बढ़ रहा है क्रेज

हिलव्यू समाचार

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखावार सामाजिक सर्वेक्षण करने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। संघ ने अपने स्वयंसेवकों को शाखा क्षेत्र में सामाजिक सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं।

संघ सर्वेक्षण के आधार पर समाज को साथ जोड़कर समस्याओं का समाधान करेंगे। राजस्थान क्षेत्र संघचालक डॉ. रमेश चंद्र अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि सामाजिक सर्वेक्षण प्रयोग देश भर में शुरू हुए है। राजस्थान में भी ऐसे ही कुछ प्रयोगों की शुरुआत हुई है। अग्रवाल ने जयपुर के सांगानेर का उदाहरण देते हुए बताया कि सामाजिक अध्ययन में शाखा क्षेत्र में पाई गई समस्या का समाधान करने का प्रयास हुआ। बस्ती में सीवरेज लाइन नहीं होने से गन्दगी भी रहती थी और आए दिन झगड़े भी होते थे।

स्वयंसेवकों की अगुवाई में लगभग 12 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन डलवाने का कार्य लोक सहयोग के माध्यम से मात्र दो करोड़ रुपए (सरकारी अनुमानित खर्च 12 करोड़ रुपए) की लागत से सफलतापूर्वक किया गया। इसी तरह जोधपुर में दो जातियों के बीच लम्बे अर्से से चल रहे झगड़े को सामाजिक सर्वेक्षण के बाद निपटाया गया।

बयान से गरमाई सियासत, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मांगे माफी

रंधावा के बयान पर सड़क से सदन तक भाजपा का प्रदर्शन

हिलव्यू समाचार

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ सदन से सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने रंधावा के बयान को राजनीतिक गरिमा के खिलाफ बताते हुए विधानसभा से वॉकआउट भी किया।

विधानसभा में मंगलवार को कृषि विभाग के अनुदान की मांग पर बहस के दौरान भाजपा विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस नेता रंधावा के बयान को लेकर हमला बोला। बहस के दौरान जैसे ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां का भाषण समाप्त हुआ, भाजपा ने अचानक इस मुद्दे को उठाया और शोर-शराबा किया। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने कहा कि जनता डरी हुई है और सरकार खामोश बैठी है। दिलावर ने कहा प्रदेश में आतंकी घुस आए हैं। जनता आतंकित है। उस आतंकवादी ने कहा है कि मोदी को खत्म कर दो। आतंकवादियों को सरकार ने अब तक नहीं पकड़ा है। सरकार चुपचाप बैठी हुई है। मोदी जी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी को मारने की साजिश हो रही है। दिलावर के साथ भाजपा के और भी कई विधायक खड़े हो गए और शोर-शराबा करने लगे। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी विधायकों ने 'सुखजिंदर सिंह रंधावा मुर्दाबाद' के नारे लगाए। कुछ देर हंगामे के बाद रंधावा के बयान के खिलाफ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सदन से बहिर्गमन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रंधावा ने प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की टिप्पणी की, वह निंदनीय है। हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि रंधावा ने मोदी को हराने और देश को बचाने की बात कही थी। उन्होंने मोदी जी को खत्म करने की बात नहीं की। मैं वहां मौजूद था।

भाजपा ने कहा माफी मांगे रधांवा

कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने रंधावा से माफी की मांग की। भाजपा के कार्यकर्ता पहले संजय सर्किल पर एकत्र हुए फिर कांग्रेस मुख्यालय की ओर कूच किया। पीसीसी के बाहर भाजपा के कार्यकर्ताओं को बैरिकेट्स लगाकर पुलिस ने पहले ही रोक लिया, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए गहलोत सरकार शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो आदि जैसे नारे लगाए।

भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे

जिलाध्यक्ष राघव शर्मा ने कहा एक ओर जहां देश की जनता ऐसे प्रधानमंत्री मोदी को युग-युग जीने का आशीर्वाद दे रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ऐसे उच्च पदों पर बैठे प्रभारी के देश के प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों से संबोधित करना शोभा नहीं देता है। राघव शर्मा ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ,70 वर्षों से जिन्होंने भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचाया, जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, ऐसी पार्टी के नेता ऐसे ही शब्द बोल सकते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें सद्बुद्धि दे। मंगलवार को पीसीसी के पास धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष राघव शर्मा के अलावा रामानंद गुर्जर, जितेंद्र शर्मा, महामंत्री कृष्ण मोहन शर्मा, कुलवंत सिंह, उपाध्यक्ष अजय पारीक, अनिल शर्मा, ब्रह्म कुमार सैनी जिले के पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र कालवी का निधन

जयपुर। राजपूत करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का सोमवार रात हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स ने रात करीब दो बजे इसकी पुष्टि की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनियां, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है।

राजस्थान विधानसभा: वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांग

15 स्थानों को घोषित किया गया इको सेंसेटिव जोन

हिलव्यू समाचार

जयपुर। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि सरकार ने नई वन नीति का अनुमोदन कर 20 प्रतिशत भूमि को वन आच्छादित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2022-23 में 56 हजार 410 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जा चुका है तथा वर्ष 2023-24 में विभिन्न विभागीय योजनाओं में 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जाएगा। चौधरी बुधवार को विधानसभा में वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने वन एवं पर्यावरण विभाग की 16 अरब 78 करोड़ 24 लाख 36 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी। चौधरी ने बताया कि वर्ष 2018 में राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91 प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत था, जो वर्तमान में बढ़कर 3.92 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के संरक्षित क्षेत्रों के लिए 24 स्थानों मे से 15 क्षेत्रों को इको सेंसेटिव जोन के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। वर्ष 2023-24 में फ्रांस सरकार के सहयोग से राज्य के 13 जिलों में 1 हजार 693 करोड़ की राजस्थान मानविकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी। वहीं जाइका के सहयोग से एक हजार 803.42 करोड़ रुपए की एक परियोजना राज्य के 19 जिलों के लिए तैयार की जा रही है।

9 नए कन्जर्वेशन रिजर्व किए गए घोषित

वन मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 9 नए कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए हैं। रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकुन्दरा टाइगर हिल्स के बाद रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही धौलपुर में एक टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। चौधरी ने बताया कि वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों, जन सहयोग से ट्री आउट साइड फोरेस्ट इन राजस्थान नाम से वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ पौधे तैयार कर वितरित किए जाएंगे।

हर जिले में लव कुश वाटिका

वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने बताया कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक लव कुश वाटिका विकसित की जा रही है। वर्ष 2023-24 में हर जिले में एक-एक लव कुश वाटिका और विकसित की जाएगी। साथ ही शहरी क्षेत्र में आगामी वर्ष में 32 करोड़ रुपए के कार्य करवाकर ग्रीन लंग्स क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

जल जीवन मिशन की समीक्षा

सुनिश्चित करें न हो पेयजल संकट, CM ने अधिकारियों को दिए निर्देश

हिलव्यू समाचार

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों और छितराई बसावट के बावजूद राज्य सरकार जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा करने में कोई कमी नहीं रख रही है। यह 'हर घर जल' के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर पेयजल समस्या का समाधान कर रही है। उन्होंने वृहद् जल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कर सुलभ पेयजल उपलब्धता और कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में गहलोत ने कहा कि प्रदेश में स्थायी जल स्त्रोतों का भी विकास सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में पेयजल की समस्या नहीं आए। प्रदेश में विगत दिनों में जल जीवन मिशन के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। इस मिशन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न स्तरीय स्वीकृतियों का समय न्यूनतम करें, जिससे धरातल पर शीघ्र काम शुरू हो सके। उन्होंने प्रदेश में अवैध कनेक्शन, बूस्टर के इस्तेमाल और लाइनों को क्षतिग्रस्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

11 जिलों के 5739 गांवों के लिए 5 वृहद् परियोजनाएं

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार को 5 वृहद् परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए पत्र भेजा गया है। इनकी स्वीकृति मिलने तथा कार्य पूरा होने से अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सीकर और झुंझुनूं के 5739 गांवों को पानी मिलेगा। इसमें 23,941 करोड़ रुपए लागत प्रस्तावित है। बैठक में बाड़मेर जिले के चौहटन, गुड़ामालानी, धोरीमन्ना व सिणधरी, झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी एवं सूरजगढ़, दौसा, सवाई माधोपुर, ईसरदा बांध से पेयजल आपूर्ति पर चर्चा हुई। वहीं कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना, परवन बांध आधारित पेयजल परियोजना, नवनेरा बैराज, चंबल-धौलपुर-भरतपुर वृहद् पेयजल परियोजना, चंबल नदी से बेगूं, निम्बाहेड़ा एवं चित्तौड़गढ़ पेयजल परियोजना, चंबल भीलवाड़ा परियोजना, चम्बल-अलवर-भरतपुर परियोजना सहित विभिन्न परियोजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, जल जीवन मिशन के प्रबंध निदेशक अविचल चतुर्वेदी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

वित्तीय प्रगति में भी राजस्थान आगे

आमजन को सुलभ पेयजल उपलब्धता के लिए जल जीवन मिशन में अभी तक 13 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में चौथे स्थान पर है। गत वित्तीय वर्ष में 3488 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2022-23 में अभी दोगुनी राशि 6700 करोड़ रुपए व्यय हो चुकी है। इस वर्ष में लगभग 7500 करोड़ रुपए व्यय लक्षित है।

रोजाना दिए जा रहे 8 हजार जल कनेक्शन

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने बताया कि मिशन में प्रतिदिन जल कनेक्शन देने में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। राज्य में फरवरी 2023 में औसतन 7142 कनेक्शन प्रतिदिन दिए गए। वहीं मार्च 2023 में औसतन 8000 कनेक्शन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा है। विभाग द्वारा मई 2022 की तुलना में फरवरी 2023 में औसतन प्रतिदिन 6 गुना अधिक कनेक्शन दिए गए हैं। अभी तक लगभग 36.28 लाख कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान की इस प्रगति को केंद्र सरकार द्वारा भी सराहा गया है।

सीएम के काफिले का रास्ता रोका... इंटेलिजेंस बेख़बर

सीएम की गाड़ी रोक गेट खोलने की कोशिश, सुरक्षा में बड़ी चूक

हिलव्यू समाचार
जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय में छात्र संघ उद्घाटन में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सुरक्षा में बड़ी चूक दिखाई दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने न केवल मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए, बल्कि उनके काफिले को रोक भी दिया। विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्र मुख्यमंत्री की सफारी कार तक पहुंच गए और उसका गेट खोलने का प्रयास भी किया।

राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर यकायक हुई इस घटना से सुरक्षाकर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री के साथ चल रही सिक्योरिटी ने छात्रों को खींच कर सीएम की गाड़ी से दूर किया। आनन-फानन में मुख्यमंत्री के काफिले का वहां से निकाला गया। यह घटनाक्रम एक मिनट से भी ज्यादा चलता रहा। इस घटना ने एक तरफ जहां पुलिस के खुफिया तंत्र की पोल खोल कर रख दी, वहीं मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगा दिया है।

रोका काफिला...

दिखाए काले कपड़े...

पुलिस ने खदेड़ा...

धरी रह गई सुरक्षा व्यवस्था

मुख्यमंत्री के विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय कॉलेज के उद्घाटन समारोह में आने के कार्यक्रम के चलते पुलिस ने चाकचौबंद व्यवस्थाओं का दावा किया था। करीब 500 से अधिक पुलिस के जवान चप्पे-चप्पे पर तैनात किए गए थे। इसके बावजूद भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए प्रदर्शनकारी सीएम की गाड़ी तक पहुंच गए।

“ एबीवीपी ने अपने संस्कारों को प्रदर्शित किया हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार हैं, लेकिन वो जायज मांगों के लिए होना चाहिए। परिषद ने जो किया, वो बेहद निंदनीय है। मुख्यमंत्री की जनकल्याणकारी योजनाओं से बीजेपी और छात्र संगठन में बौखलाहट दिखाई दे रही है। ये हरकत निहायत कायराना है। **अभिषेक चौधरी,** प्रदेश अध्यक्ष, NSUI

सरकार वीरांगनाओं की नहीं सुन रही

सीएम गहलोत को काले झंडे दिखाने के बाद विद्यार्थी परिषद के प्रान्त मंत्री शौर्य जैमन ने कहा कि सरकार लगातार वीरांगनाओं का अपमान कर रही है और उनकी सुनवाई नहीं कर रहीं हैं। सरकार ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों की वीरांगनाओं को नजर बंद करके रखा हुआ है। वीरांगनाओं के सम्मान में परिषद खड़ी है। वीरांगनाओं के सम्मान में 21 मार्च को गुर्जर की थड़ी पर प्रदर्शन किया जाएगा और सिविल लाइंस की तरफ कूच किया जाएगा। लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है।

बिल पास करने की एवज में मांगी घूस

सरपंच को तीन लाख रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

हिलव्यू समाचार
झालावाड़। बकानी पंचायत समिति क्षेत्र की देव नगर पंचायत का सरपंच मंगलवार को तीन लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी के हत्थे चढ़ गया। ब्यूरो की टीम ने सरपंच को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सरपंच रामबाबू मेघवाल ने पंचायत क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के बिल पास करने की एवज में परिवादी से रिश्वत की मांग की थी। सरपंच परिवादी के घर पहुंचकर रिश्वत की राशि ले रहा था। इसी दौरान एसीबी टीम ने योजनाबद्ध रूप से घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ एसीबी टीम ने बताया कि परिवादी और पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी बालमुकुंद गुर्जर ने झालावाड़ एसीबी को शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि पिछले सप्ताह के दौरान पंचायत में मनरेगा योजना के तहत कई विकास कार्य करवाए गए थे। इनके बकाया 46 लाख रुपए के बिल पास करने की एवज में सरपंच सात प्रतिशत के हिसाब से 3 लाख रुपए की मांग कर रहा था। परिवादी से मिली शिकायत के बाद एसीबी टीम ने मामले का सत्यापन करवाया और सरपंच रामबाबू को परिवादी के घर पर रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एसीबी टीम आरोपी सरपंच से पूछताछ करने में जुटी हुई है।

विधानसभा में MLA लोढ़ा ने धारीवाल से पूछा- भाजपा से क्या याराना, दिव्या भी बरसीं

हिलव्यू समाचार
जयपुर। विधानसभा में गत बुधवार को नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को सत्ता पक्ष के विधायकों के तीखे तेवरों से दो-चार होना पड़ा। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा नेताओं के साथ धारीवाल के संबंधों का आरोप लगाया। लोढ़ा ने सिरोही में भाजपा कार्यालय के लिए 50 करोड़ की जमीन देने के मामले को घोटाला बताते हुए धारीवाल से पूछा कि आखिर आपका भाजपा से क्या याराना है? संयम के आरोपों पर भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। इससे सदन में करीब 10 से 15 मिनट तक व्यवधान तक रहा। वहीं, कांग्रेस की ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा भी जमकर गरजीं।

विधायक दिव्या मदेरणा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 44 सड़कों का काम रोकने के विरोध में धारीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि अगर काम रोकने की जिद पर मंत्री जी अड़ ही गए हैं तो वे भी वीरांगनाओं की तरह मुंह में घास लेकर धरने पर बैठ जाएंगी और अगर मंत्री जी में दम हो तो रात के तीन बजे उन्हें उठा कर दिखा दें। दिव्या ने कहा कि मैंने किरोड़ी लाल मीणा को आतंकी कहने का विरोध और वीरांगनाओं का समर्थन किया था, क्या इसका बदला मंत्री जी मुझसे ले रहे हैं ? तो मैं कह दूं कि मैं वह शख्स हूं जो अपने बलबूते पर हूं, मैं किसी की हां में हां नहीं मिला सकती।

लोढ़ा ने राठौड़ से कहा... घोटाले में आपका नाम भी

लोढ़ा ने राजेंद्र राठौड़ से कहा कि तब आप सिरोही के प्रभारी मंत्री थे। इस 50 करोड़ के घोटाले में आपका भी नाम है। इस पर राठौड़ बोले कि सदन तो बगैर व्यवस्थाओं के ही चल रहा है। लोढ़ा बगैर किसी सबूत के आरोप कैसे लगा सकते हैं और जो मामला कोर्ट में लंबित है उसका कार्यवाही में जिक्र कैसे कर सकते हैं? राठौड़ ने यह भी कहा कि मैं प्रभारी मंत्री था, लेकिन आपकी छाती पर मूंग दलने के लिए फिर आ रहा हूं।

धारीवाल से कहा... आपको भी जेल भेजने के जतन हुए थे

लोढ़ा ने धारीवाल से कहा कि जब राजे की सरकार थी, उस समय यही आपको जेल में डालने के लिए क्या-क्या जतन कर रही थीं। लेकिन, आपकी सरकार के समय पर घोटाले की जमीन पर क्या कार्रवाई की गई। संविधान में साफ लिखित है कि कोई भी पूर्व सीएम, या पूर्व में किसी पद पर बैठा व्यक्ति सरकार की तरफ से दिए गए उस बंगले में नहीं रह सकता तो फिर आप क्यों सरकारी बंगले को वापस नहीं लेते?

वसुंधरा राजे पर ज़मीन घोटाले का आरोप

संयम लोढ़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री राजे के कार्यकाल के दौरान जमीन घोटाले करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं बगैर सबूत के कुछ नहीं कहता। मेरे पास सारे सबूत है कि राजे ने राजस्थान में जमीनों का कितना घोटाला किया है। लोढ़ा के आरोपों का विरोध करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत भाजपा विधायकों ने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार हंगामा किया।

एक नज़र

चंडीगढ़ से ले जाई जा रही थी गुजरात

तीस लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी, तस्कर गिरफ्तार

हिलव्यू समाचार
अजमेर। जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। माखुपुरा क्षेत्र में नाकाबंदी कर अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा गया। ट्रक से 30 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब जब्त की गई है। वहीं पुलिस चालक को गिरफ्तार कर मुख्य तस्कर की तलाश कर रही है। सहायक आबकारी अधिकारी बंकट सिंह ने बताया कि मुखबिर से अवैध शराब तस्करी को लेकर सूचना मिली थी। इस पर नाकाबंदी कर माखुपुरा में पुलिया के पास हरियाणा नम्बर के ट्रक को रुकवाया गया। उसके चालक ने ट्रक में टायर की रिम भरी होने की बात कहते हुए बिल्टी दिखाई। उसके हाव-भाव से टीम को संदेह हुआ। जब पुलिस ने ट्रक का तिरपाल हटवाकर अंदर देखा तो उसमें शराब भरी मिली। इस पर ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया गया। ट्रक से विभिन्न ब्रांड की कुल 467 पेटी शराब बरामद की गई। इसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। मामले में उत्तरप्रदेश के मुजफ्फर नगर निवासी आरोपी सतनाम सिंह के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी ने चंडीगढ़ से सूरत शराब की तस्करी करने की बात कबूल की है। वहीं मुख्य तस्कर के संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

विलायती बबूल से मिलेगी निजात

प्रदेश मोटे अनाज के उत्पादन में देश में अग्रणी: मंत्री कटारिया

हिलव्यू समाचार
जयपुर। कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री लालचन्द कटारिया ने कहा है कि राजस्थान मिलेट्स के उत्पादन में देश में अग्रणी है। आने वाले समय में मोटे अनाज की मांग बढ़ने से प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि विभाग विलायती बबूल की समस्या से निजात दिलाने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर प्रभावित जमीन पर फलदार पौधे लगाएगा।

कटारिया मंगलवार को विधानसभा में कृषि विभाग तथा पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने कृषि विभाग की 37 अरब 48 करोड़ 99 लाख 36 हजार रुपए तथा पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की 14 अरब 55 करोड़ 48 लाख 27 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी गईं। कटारिया ने बताया कि राज्य सरकार ने कृषकों एवं पशुपालकों के कल्याण के लिए बड़े स्तर पर योजनाएं संचालित की हैं। उन्होंने बताया कि आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए तारबंदी योजना को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। जिसमें 15 हजार किसानों को अनुदान देकर 45 लाख मीटर की तारबंदी किया जाना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत गत 4 वर्ष में 11 हजार करोड़ रुपए का राज्यांश भुगतान किया गया है।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में दीक्षान्त समारोह

दूरस्थ शिक्षा में वोकेशनल-प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों पर दें जोर: राज्यपाल

हिलव्यू समाचार
जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि उच्च शिक्षा में नवाचारों के मूल में शोध होते हैं, शोध मानकों को बदल कर हमें समाजोपयोगी बनाने होंगे। उन्होंने कहा कि दूरस्थ शिक्षा में साधारण पाठ्यक्रमों के अलावा वोकेशनल और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की पढ़ाई पर और जोर दिया जाना चाहिए, जिससे बेरोजगारी दूर की जा सके।

राज्यपाल गत मंगलवार को संत सुधासागर सभागार में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षान्त समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दूरस्थ शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी के समय विश्वविद्यालयों में जब ताले लगे थे तो दूरस्थ शिक्षा के केन्द्र घर बैठे विद्यार्थियों को ऑनलाइन किताबें और वीडियो लेक्चर के जरिए मदद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय छात्रों को घर बैठे शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो दूरस्थ गांवों तक उच्च शिक्षा का उजियारा पहुंचेगा।

32 में से 23 स्वर्ण पदक छात्राओं को मिलना शुभ संकेत

राज्यपाल ने कहा कि समारोह में 32 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए हैं जिनमें 23 स्वर्ण पदक छात्राओं ने प्राप्त किए हैं, यह भारत के लिए शुभ संकेत है। छात्राओं को अवसर मिले तो वे देश को आगे बढ़ाने में नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ढांचा लागू किया गया है वह वास्तव में भारतीय जीवन मूल्यों और संस्कृति को आलोकित करने वाला है। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इन सभी बातों का समावेश किया है। उन्होंने कहा कि समय की आवश्यकता को देखते हुए विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में बदलाव हो रहे हैं, इसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा।

सभागार का किया लोकार्पण

विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर नवनिर्मित संत सुधासागर सभागार का लोकार्पण किया गया। सांसद एवं विधायक कोष की राशि से बने सभागार का निर्माण श्रीदिगम्बर जैन भगवान महावीर संस्थान कार्यकारी एजेंसी द्वारा कराया गया है। इस अवसर पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त राजपाल सिंह, पुलिस अधीक्षक (शहर) शरद चौधरी, ग्रामीण कावेन्द्र सिंह, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अभय कुमार व्यास, तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रो. एसके सिंह, कोटा विश्वविद्यालय के कुल सचिव केके गोयल, सभी अधिष्ठाता, निदेशकगण एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

शोध का किसानों को मिले फायदा

राज्यपाल ने कहा विश्वविद्यालयों को शोध 'लैब-टु-लैंड' प्रोग्राम चलाकर किसानों के हित में अनुसंधान करते हुए उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए कार्य करना होगा। उन्होंने कहा गांव हमारी सामाजिक भागीदारी के हिस्से हैं। विश्वविद्यालयों की ओर से गांवों को गोद लिए जाने की परंपरा शुरू की गई थी। इसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने दीक्षार्थियों का आह्वान किया कि जो ज्ञान गुरुजनों से अर्जित किया है उससे आप अपने अंदर नैतिक गुण विकसित करें।

मरीजों को हाइटेक सुविधाएं देने में पीछे नहीं एसएमएस अस्पताल

SMS में हाइड्रो सर्जरी जल्द ही, बिना बेहोश करे होंगे ऑपरेशन

हिलव्यू समाचार

जयपुर। मरीजों को हाइटेक सुविधाएं देने में प्रदेश का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह अस्पताल पीछे नहीं है। रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू करने वाले एसएमएस अस्पताल में अब एक और नई तकनीक से ऑपरेशन कर मरीजों को राहत देने की तैयारी है। सर्जरी विभाग जल्दी ही हाइड्रो सर्जरी सिस्टम की सुविधा पेशेंट को देगा। इसमें डाइबिटिक फुट, गैंगरीन, अल्सर इत्यादि बीमारियों से पीड़ित मरीजों के ऑपरेशन बगैर बेहोश किए हो सकेंगे। इसमें एनेस्थेसिया की डोज देने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही बिना दर्द के कम समय में सर्जरी हो सकेगी। वहीं, जिन मरीजों के डिब्राइडमेंट बार-बार करने पड़ते हैं, उनके ऑपरेशन एक बार में ही हो सकेंगे।

डायबिटिक फुट अल्सर के लक्षणों में पैरों के स्किन का रंग का बदलना, पैरों में सूनापन और सनसनाहट होना, पैरों में संवेदनशीलता का कम होना, घाव होना, घाव से गंदगी निकलना चलने में पैर दर्द होना आदि परेशानी होती है। डायबिटीज की वजह से पैरों में घाव हो जाते हैं, जिसे सर्जरी के जरिए ठीक किया जाता है। चिकित्सकों का कहना है कि डायबिटीज की वजह से पैरों में होने वाला घाव बढ़ता रहता है। रक्त कोशिकाओं में थक्के जमा हो जाते हैं और ये कोशिकाएं ब्लॉक हो जाते हैं। इस अवस्था में रोगी के पैरों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और इसी कारण से उंगलियों, पैर में गैंगरीन हो जाती है। ऐसे मरीजों वेन्स सिकुड जाती है या वसा के थक्के के कारण कई स्थानों पर ब्लॉक हो जाती है। नई तकनीक से ऑपरेशन मरीजों के लिए कारगर होगा, क्योंकि इसमें दर्द से निजात मिलेगी साथ ही बार-बार सर्जरी की आवश्यकता भी खत्म होगी।

इमरजेंसी ओटी में भी हो सकेगी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी

एसएमएस सर्जरी विभाग में लेजर व हायड्रो सर्जरी सिस्टम से ऑपरेशन होंगे। साथ ही इमरजेंसी ओटी में भी अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकेगी। अस्पताल अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा ने बताया कि हमारे यहां एंडोवेनस लेजर सिस्टम से ऑपरेशन होने शुरू हो गए हैं। इससे पाइल्स, फिस्टुला, पाइलोनिडियल साइनस वेरिकोस बेन्स आदि बीमारियों से ग्रमित मरीजों के ऑपरेशन जल्दी व कम चीर फाड़ व बिना दर्द के हो सकेंगे। सीनियर प्रोफेसर डॉ. राजेन्द्र मांडिया ने बताया कि अब इमरजेंसी में भी गंभीर मरीजों के ऑपरेशन के लिए लेप्रोस्कोपिक तकनीक की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए इमरजेंसी ओटी में लेप्रोस्कोपिक सेट लगा दिया गया है।

रोबोटिक सर्जरी वाला पहला मेडिकल कॉलेज

एसएमएस प्रदेश का ऐसा पहला मेडिकल कॉलेज बन गया है, जहां यूरोलॉजी व जनरल सर्जरी विभाग में मरीजों की रोबोटिक सर्जरी हुई। विभागाध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र मांडिया ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह 360 डिग्री तक सूचरिंग कर सकता है और जो काम लेप्रोस्कोपिक में नहीं हो सकता वह रोबोट से कराया जा सकता है।

चंबल रिवर फ्रंट पर कुल 26 फाउंटेन किए गए विकसित

हिलव्यू समाचार

कोटा। कोचिंग सिटी कोटा को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य से हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट की सौगात देश और दुनिया के पर्यटकों को जल्द मिलने जा रही है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में रिवर फ्रंट पर स्थापित किए जा रहे मॉन्यूमेंट्स सहित अन्य इमारतों का कार्य अंतिम चरण में है। वहीं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने वाले चंबल रिवर फ्रंट पर स्थापित किए जा रहे फाउंटेन भी विश्व स्तरीय पहचान बनाएंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि चंबल रिवर फ्रंट कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में विश्व स्तरीय पहचान दिलाने वाला प्रोजेक्ट साबित होगा हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा प्रोजेक्ट साइट की विजिट के बाद उन्होंने भी इसकी सराहना की है। रिवर फ्रंट पर कुल 26 फाउंटेन विकसित किए जा रहे हैं जो देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। स्पेन के बार्सिलोना के मैजिक फाउंटेन की तर्ज पर कोटा में बैराज गार्डन पर फाउंटेन विकसित किया गया है। इसी प्रकार अन्य इमारतों में भी प्रदेश की शिल्प कला का मनोहारी नजारा दिखाई देगा।

फाउंटेन में 9 तरह के इफेक्ट आएंगे नजर

न्यास सचिव राजेश जोशी ने बताया कि चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अब जल्द पूर्ण होने जा रहा है। यहां कई विश्व कीर्तिमान तो स्थापित हो ही रहे हैं। यहां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने वाले फॉर्मटेन भी विश्व रिकॉर्ड होगा। चंबल रिवर फ्रंट पर लगभग 26 फाउंटेन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें ऐतिहासिक बावड़ी का फाउंटेन टेस्टिंग हो चुकी है। बैराज गार्डन के फाउंटेन को स्पेन देश के बार्सिलोना मैजिक फाउंटेन की तर्ज पर बनाया गया है, जिसमें लगभग 154 पंप हैं जो की 751 hp के है साथ ही लगभग 9 तरह के इफेक्टस फाउंटेन की क्षमता और उसके आकर्षण को बयां करेंगे।

राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव-2023 का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन

कृषि अनुसंधान के परिणाम स्वरूप हरित क्रांति का आगाज

हिलव्यू समाचार

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कृषि अनुसंधान के परिणाम स्वरूप हरित क्रांति का आगाज हुआ, जिसके सफल नतीजे हमारे देश ने प्राप्त किए और हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान से किसानों को भविष्य के लिए अपनी फसल तैयार करने में लाभ मिलेगा। कॉन्क्लेव में मिलेट्स का बेहतर उत्पादन, प्रबंधन और विपणन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण सुझाव सामने आएंगे।

सीएम ने कहा कि किसानों के सर्वांगीण विकास की योजनाएं लागू करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। कृषक कल्याण और कृषि क्षेत्र विकास में राज्य सरकार ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। विधानसभा में दो बार पृथक कृषि बजट पेश कर पूरे देश में ऐतिहासिक पहल की। उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालकों को उचित सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। सोमवार को दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव-2023 में गहलोत ने कहा कि मिलेट्स की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और कृषि अनुसंधान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्थान में मिलेट्स पर रिसर्च के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है।

राजकिसान सुविधा एप लॉन्च

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजकिसान सुविधा एप लॉन्च किया। इसमें योजनाओं के आवेदन और उनकी स्थिति जानी जा सकेगी। साथ ही, गहलोत ने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 की सफलता की कहानियों से संबंधित बुकलेट का विमोचन भी किया। इस दौरान 'समृद्ध किसान-खुशहाल राजस्थान' लघु फिल्म भी दिखाई गई।

मिलेट्स स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि मिलेट्स कुपोषण दूर करने में सहायक है। कोरोनाकाल में हुए शोध में भी इसकी महत्ता सामने आई। सरकार ने गत 4 सालों में कृषि क्षेत्र में देशव्यापी नवाचार हुए हैं। उन्होंने कहा कि मिलेट्स फूड आज हर शादी समारोह में परोसे जा रहे हैं।

'आप' का जयपुर में शक्ति प्रदर्शन

'सीएम गहलोत व पूर्व सीएम राजे में सांठगांठ, दोनों की अच्छी बनती है'

हिलव्यू समाचार

जयपुर। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गत सोमवार को जयपुर में तिरंगा यात्रा निकालकर प्रदेश में 'आप' की चुनावी गतिविधियों का आगाज किया। केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों के बीच सत्ता की लड़ाई है। ये लोग आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच सांठगांठ होने का तंज कसते हुए कहा कि मैंने सुना है कि राजस्थान में गहलोत और राजे की बहुत अच्छी बनती है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है। गहलोत को थोड़ी सी आंच आ जाए तो वसुंधरा उनके लिए पूरी बीजेपी खड़ी कर देती है। बीच में एक बात फैली थी कि बीजेपी वाले वसुंधरा राजे को हटा रहे हैं तो गहलोत ने राजे के समर्थन में पूरी कांग्रेस लगा दी थी। ये अलग-अलग नहीं, एक ही पार्टी है। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत पार्टी। ऐसे में यह तो साफ है कि सरकार किसी की बना लो, चलेगी तो इन दोनों की ही। इस बार आम आदमी पार्टी ले आओ। मुझे और मान को राजनीति करनी नहीं आती है, हमें तो स्कूल, अस्पताल और सड़क बनवानी आती है। सिर्फ हमें तो जनता की सेवा करना आता है। आप' ने सांगानेरी गेट से अजमेरी गेट तक तिरंगा यात्रा निकाली।

चोर-चोर मौसेरे भाई

केजरीवाल ने कहा कि दोनों पार्टियां चोर-चोर मौसेरे भाई। कोई कह रहा था कि दोनों भाई-बहन हैं। जब बीजेपी की सरकार आती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि इन्होंने खूब घोटाले किए। तो जनता सोचती है कि इस बार इनको मौका दो। लेकिन, सत्ता में आते ही कोई जेल नहीं जाता है और ये भी जनता को लूटना शुरू कर देते हैं। अब तक दोनों ने किसी को भी जेल नहीं भेजा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस ने 48 और बीजेपी ने 18 साल राज किया है। लेकिन, दोनों ही पार्टियां ये नहीं कह सकती कि हमने इनको मौका नहीं दिया। इससे पहले एयरपोर्ट पर राजस्थान में आप पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि सारे चेहरे भी आएंगे, थोडा सा इंतजार कीजिए। यह हमारी पहली यात्रा है और कुछ दिनों बाद जब दोबारा मिलेंगे तो आप देखेंगे कि एक मजबूत संगठन बन गया होगा।

अब राजस्थान की बारी

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस ने 5-5 साल की पारी खेलकर जनता का लूटा। हमको लगा कि अब पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है तो सुधर गई होगी। लेकिन, दोबारा आते ही फिर से जनता को लूटना शुरू कर देती है। पहले हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन, अब भगवान ने एक झाड़ू भेज दिया है, जो ये गंदगी की सफाई करेगा। आप ने दिल्ली में दो बार कांग्रेस और पंजाब में एक बार बीजेपी की सफाई की। अब हमारी पार्टी राजस्थान में भी झाड़ू चलाने के लिए तैयार है।

ब्लॉकों की नीलामी का बनाया जाएगा त्रैमासिक कैलेंडर

जयपुर। एक अप्रेल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष में प्रदेश में मेजर और माइनर खनिज ब्लॉकों की नीलामी का वार्षिक रोडमैप तैयार करते हुए ब्लॉकों की नीलामी का त्रैमासिक कैलेंडर बनाया जएगा। अति. मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि इस कदम से नीलामी के लिए माइनिंग ब्लॉक तैयार करने से लेकर नीलामी तक का एक्शन प्लान तय करने के साथ ही मॉनिटरिंग भी हो सकेगी। वहीं विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम बनाकर उड़ीसा की व्यवस्था का अध्ययन करवाया जाएगा। जिससे वहां की बेस्ट प्रेक्टिसेज को राजस्थान के संदर्भ में उपयोगी पाए जाने पर अपनाया जा सके। एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने सचिवालय में माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि खान सुरक्षा और सिलिकोसिस को लेकर विभाग गंभीर है और इसी का परिणाम है कि सिलिकोसिस जांच, जागरुकता शिविरों के नियमित आयोजन के साथ ही खान सुरक्षा मापदंडों की पालना के लिए खानों का निरीक्षण करवाया जा रहा है। निदेशक माइंस संदेश नायक ने बताया कि विभाग पिछले साल 6395 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन को पीछे छोड़ते हुए इस साल राजस्व अर्जन का नया रिकॉर्ड बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है।

राहत की खुली राह: तीन माह पहले हाई कोर्ट ने किया था रजिस्ट्रार जनरल को तलब

जेडीए बनाएगा हाई कोर्ट के सामने 500 वाहनों की पार्किंग

हिलव्यू समाचार

जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर सड़क पर बेतरतीब खड़े रहने वाले वाहनों से निजात के लिए जेडीए 500 वाहन क्षमता की भूमिगत पार्किंग बनाएगा। सड़क पर वाहनों की पार्किंग को लेकर हाई कोर्ट ने कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को तलब किया था। इसके तीन महीने बाद अब जेडीए ने पार्किंग के लिए कवायद शुरू की है।

गौरतलब है कि यहां पार्किंग की समस्या के चलते आए दिन लगने वाले जाम से निपटने के लिए गत सोमवार को जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित हुई। दरअसल कोर्ट परिसर के बाहर वाहन पार्किंग के चलते लगने वाले लम्बे जाम को देखते हुए कोर्ट में नवम्बर 2022 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा था। जेडीए ने यहां जमीन देखना शुरू कर दिया है। अभी आमजन को यहां पार्किंग की सुविधा के लिए साल भर का इंतजार करना पड़ेगा।

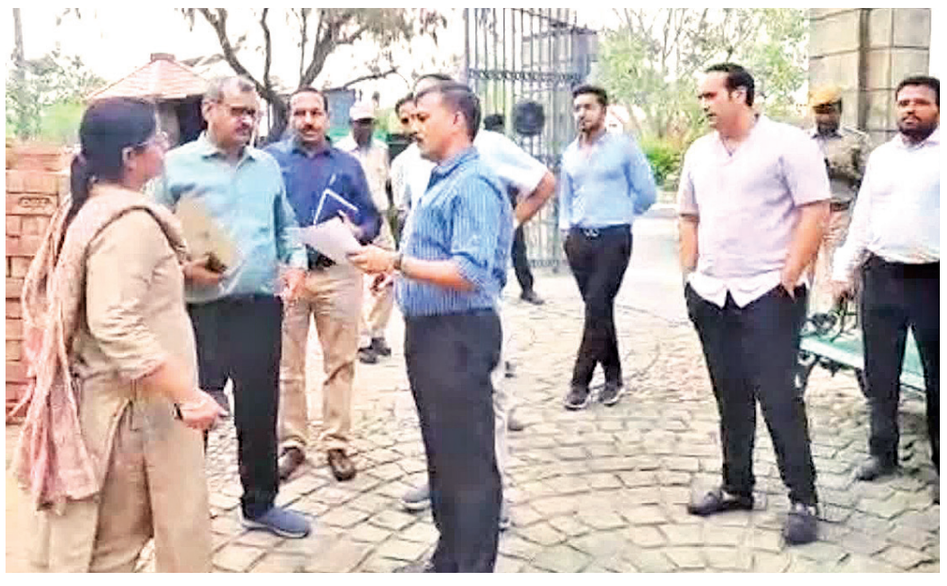

आमजन को भमिगत पार्किंग का लाभ अगले वर्ष मार्च तक मिलने लगेगा। अभी हाईकोर्ट के सामने जमीन का निरीक्षण किया जाना है। उसके बाद टेंडर प्रोसेस शुरू होगी, जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आमजन को हो रही पार्किंग की परेशानी से जल्द राहत मिलेगी।

रवि जैन, जयपुर विकास आयुक्त

आएगी 50 करोड़ रुपए की लागत

हाई कोर्ट के सामने लम्बे वक्त से जाम की स्थिति से आमजन को निजात दिलाने के लिए जेडीए की ओर से 50 करोड़ की लागत से भूमिगत पार्किंग बनाई जाएगी। इस पार्किंग के बनने के बाद यहां करीब 500 वाहन पार्क हो सकेंगे। गौरतलब है कि कोर्ट आने वाले वकीलों के अलावा हाई कोर्ट का यह रास्ता जयपुराइट्स को विधानसभा से एमआई रोड होते हुए शहर से जोड़ता है। यहां से हजारों लोग दिनभर वाहन लेकर गुजरते हैं।

याचिका में मांगा था जवाब

हाई कोर्ट परिसर में वकीलों सहित अन्य लोगों के लिए पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर कोर्ट में नवम्बर में याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट के आस-पास का यह वीआईपी एरिया है। यहां हाई कोर्ट के अलावा विधानसभा और सचिवालय सहित अन्य सरकारी विभाग मौजूद हैं। इस रोड से मुख्यमंत्री सहित अन्य वीआईपी लोग भी गुजरते हैं। याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट परिसर के पास ही इंदिरा गांधी नगर परियोजना के भवन को पार्किंग के काम लिया जा सकता है। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल से जवाब तलब किया था।

‘क्वालिटी लाइफ’ के दौर में

युवाओं का चरित्र इतना ‘कमज़ोर’ क्यों ?

मेडिकल सुविधा, पढ़ाई, यातायात, नौकरी, कृषि, दफ्तरी कामकाज, बागवानी आदि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इंसान ने हाल के दशकों में बहुत उन्नति न की हो. हालांकि एक क्षेत्र ऐसा है जहां हर गुजरते दिन के साथ इंसान और ज्यादा कमजोर, अविश्वसनीय, घातक और खतरनाक हुआ है. आखिर क्यों?...आइए, पड़ताल करते हैं.

अगर विज्ञान और तकनीक की प्रगति के नजरिये से देखें तो यह दौर मानव इतिहास का सबसे उन्नत दौर है. कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इंसानी कौशल, इंसानी मेधा चमत्कारिक उपलब्धियां न हासिल कर रही हो. एक जमाना था जब हवाई यात्रा 70 से 80 फीसदी तक असुरक्षित होती थी लेकिन अब हवाई यात्रा की असुरक्षा घटकर सिर्फ 5 से 7 फीसदी रह गई है. पिछली सदी के 80 और 90 के दशक तक रेल यात्रा 5 से 7 फीसदी तक असुरक्षित थी. अब यह असुरक्षा घटकर 1 से 0.5 फीसदी रह गई है. कहने का मतलब हवाई जहाज सुरक्षित हो गए हैं. रेलगाड़ियां सुरक्षित हो गयी हैं. महामारियों में भी 20वीं सदी के मध्य तक जहां 25 से 30 फीसदी तक लोग अपनी जान गंवा बैठते थे, वह आंकड़ा अब घटकर 2 से 5 फीसदी तक आ गया है. कहने का मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इंसान ने अपनी मेधा, अपने कौशल और अपनी दिमागी कुशलता के चलते पिछले 5 दशकों में जबर्दस्त कामयाबी न हासिल की हो. हर उपभोक्ता उत्पाद आज कुछ दशकों पहले के मुकाबले ज्यादा उन्नत है. मेडिकल सुविधाएं, पढ़ाई, यातायात, नौकरियां, कृषि, दफ्तरी कामकाज, बागवानी आदि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इंसान ने हाल के दशकों में बहुत उन्नति न की हो. हालांकि एक क्षेत्र ऐसा है जहां हर गुजरते दिन के साथ इंसान और ज्यादा कमजोर, अविश्वसनीय, घातक और खतरनाक हुआ है. जी हां, यह है इंसानी चरित्र, विशेषकर इंसानी भरोसा.

नैतिकता की कसौटी पर फेल

हाल के दशकों में विज्ञान, तकनीकी कौशल विकास के सभी क्षेत्रों में इंसान ने अपना परचम लहराया है लेकिन नैतिकता की कसौटी पर वह फेल हुआ है. पूरी दुनिया में इंसानी धोखाधड़ी, विश्वासघात, हत्याएं और फ्रॉड के मामले बढ़े हैं. ऐसा कोई साल नहीं जाता जब इन तमाम क्षेत्रों में इंसान कुछ पायदान और नीचे न खिसक जाता हो. शायद भरोसा बनाने का काम मशीनों के पास नहीं है. विश्वास, भरोसा या समग्रता में कहें तो इंसानी चरित्र किसी फैक्टरी में नहीं बन रहा. इसे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट नहीं बना रहा. हिंदुस्तान में युवाओं का लगातार चारित्रिक पतन हो रहा है जबकि पिछले कुछ दशकों में हमारी साक्षरता काफी ज्यादा बढ़ी है. जीवन जीने और सपने देखने की सुविधाएं बढ़ी हैं. संचार सुविधाओं और सोशल मीडिया के कारण युवाओं में औपचारिक इंटरेक्शन तथा अवेयरनेस में भी इजाफा हुआ है. आज उनका भविष्य पहले से कहीं ज्यादा सुखद और सुरक्षित है. इस सबके बावजूद युवाओं का चरित्र मजबूत नहीं कमजोर हो रहा है. उल्टे पतन दिशा में लगातार फिसल रहा है. यह अकेले युवाओं का मामला भी नहीं है लेकिन देखने वाली बात यह है कि युवा चीजों को आगे ले जा रहे हैं, इसलिए चिंता सबसे ज्यादा उन्हीं को लेकर होनी चाहिए.

लिव इन में मारी जा रहीं लड़कियां

एक तरफ जहां सोशल मीडिया और रोजमर्रा की जिंदगी में आये खुलेपन से लड़कियों और लड़कों के बीच दूरियां कम हुई हैं, रिश्तों और भावनाओं की अभिव्यक्ति में बेबाकी आयी है लेकिन वहीं विश्वासघात में कोई कमी नहीं बल्कि उल्टे बढ़ोतरी हुई है. यद्यपि इस बात का कोई ठोस आंकड़ा तो नहीं है कि देश में कुल कितने युवा ‘लिव इन रिलेशनशिप’ में रहते हैं लेकिन अपने इर्द-गिर्द हम लिव इन रिलेशनशिप को लेकर टूटती हुई झिझक और वर्जनाओं को देख सकते हैं. मगर क्या लिव इन रिलेशनशिप में कोई मेच्योरिटी भी दिख रही है? एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में आज 22 से 28 साल के 50 फीसदी से ज्यादा युवा लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं.

बड़ा संकट भरोसे का है, ईमानदारी का है

आमतौर पर जब कुछ झकझोर देने वाले केस सामने आते हैं तब सामान्य लोगों को पता चलता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना आज भी कितना खतरनाक है वरना तो लिव इन रिलेशनशिप में होने वाली हत्याएं भी अब आम बात हो गई हैं. इन दिनों आफताब/श्रद्धा वालकर, साहिल गहलोत/निकी यादव और हार्दिक शाह/मेघा जैसे झकझोर देने वाले हत्याकांड छाए हुए हैं, इसलिए ये परेशान करते हैं वरना कोई इन पर ध्यान ही नहीं देता. मसलन एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक़ देश में हर साल 300 से ज्यादा लड़कियां अपने पार्टनर द्वारा लिव इन रिलेशनशिप में मारी जाती हैं लेकिन क्या हम इनकी चर्चा भी सुनते हैं. आखिर संकट कहां है? संकट सिर्फ भरोसे का है, ईमानदारी का है. अपवाद के तौर पर हो सकता है कुछ केस ऐसे भी हों जिनमें लडकियां भी लड़कों के साथ विश्वासघात करती हों लेकिन व्यवहार रूप में आंकड़े देखें तो लिव इन में रहते हुए 99.99 फीसदी लड़कियां मारी जाती हैं.

धोखाधड़ी में युवा सबसे आगे

यह सिर्फ रिश्तों की बात ही नहीं है. हर क्षेत्र में इंसान की गुणवत्ता क्षरित हुई है. जैसे-जैसे इंसान की बुद्धि कौशल, तकनीक और दूसरे क्षेत्रों में प्रगति हुई है, वैसे-वैसे उसका चरित्र बहुत कमजोर हुआ है. डेलॉय इंडिया की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हाल के वर्षों में बीमा और बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत तेज रफ्तार से धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं. डेलॉय इंडिया ने जिन बीमा कंपनियों से इस सर्वे में बातचीत की, उनमें से 60 फीसदी इस बात को स्वीकारते हैं कि धोखाधड़ी में इजाफा हुआ है. इस धोखाधड़ी में सबसे ज्यादा युवा शामिल हैं. ये बेईमानी और धोखाधड़ी जिस उन्नत तकनीक के बदौलत हो रही है, वह सब अधेड़ों और बूढ़ों के बस में भी नहीं है क्योंकि तकनीक के इस्तेमाल वह उतने कुशल नहीं हैं. देश में बहुत तेज रफ्तार से साइबर क्राइम बढ़ रहा है. इस साइबर क्राइम में भी युवाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी हैं.

अपनी ‘उन्नति’ के आगे बाकी बेकार...

सवाल है हमारे युवा अगर पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तकनीक को समझने और आत्मसात करने के मामले में दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है, कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष कर सफलता प्राप्त करने में भारतीय युवाओं से ज्यादा जीवट किसी में नहीं है. पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वालों में भी भारतीय युवा शामिल हैं लेकिन इतनी सारी खूबियों के बीच आखिर उनका चरित्र इतना कमजोर क्यों है? जो युवा अपने आगे बढ़ने के लिए हर तरह की मेहनत करना जानता है, हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहता है, वह युवा अपने भावनात्मक रिश्तों, सामाजिक आचरण और ईमानदाराना चरित्र के मामले में इतना कमजोर क्यों है?

▲ लोकमित्र गौतम

एच3एन2 इन्फ्लूएंजा की आफत

सजग रहें, जीत जाएंगे

जनवरी से मार्च तक वैसे भी भारत के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी-जुकाम के लक्षणों का मौसम रहता है लेकिन अगर आप इस बार इस गफलत में हैं तो सजग हो जाइये. इस बार का बुखार, रह-रहकर आने वाली खांसी और तेजी से लगने वाली सर्दी अपने पीछे कुछ और ही रहस्य छिपाये हो सकती है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि होली के 3 दिन बाद जब आमतौर पर इस तरह के संक्रमण काफी घट जाते थे, इस साल पूरे देश में 5 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में थे. यह अलग बात है कि बहुत मामूली लोगों को ही आईसीयू में भर्ती कराने की नौबत आ रही है. बावजूद इसके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने साफ़ कहा है कि लापरवाही की बिल्कुल छूट नहीं है. इससे पता चलता है कि यह साधारण सर्दी-जुकाम और नजला ही नहीं, एच3एन2 इन्फ्लूएंजा भी हो सकता है. सवाल है आम लोग जो न तो ज्यादा मेडिकल लैंग्वेज की टर्मलॉजी जानते हैं और न ही इतने अवेयर हैं, वे कैसे इस छिपे हुए एच3एन2 से बचें. आइये इसकी पूरी कहानी जानें.

फ्लू और एच3एन2 में फर्क जानें

वास्तव में जब नाक, गले के साथ-साथ फेफड़े भी जकड़ने लगें तो इस इन्फ्लूएंजा के संक्रमण की आशंका काफी ज्यादा बढ़ जाती है. 19वीं सदी के आखिरी दिनों में वैज्ञानिकों ने इस इन्फ्लूएंजा की पहचान की थी. इसमें तेज बुखार आता है. हालांकि अभी तक चीजें कंट्रोल में है लेकिन हमें खुद भी इनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा. इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि हम यह जानें कि यह मौसमी फ्लू है या खतरनाक एच3एन2. याद रखिए इन्फ्लूएंजा यानी एच3एन2 बच्चों को बहुत ज्यादा और तेजी से संक्रमित करता है. कुछ दिनों पहले तक बंगाल में 100 से ज्यादा छोटे बच्चे इसकी चपेट में थे. बच्चों में फैले इस इन्फ्लूएंजा को लेकर आशंका यही है कि यह एच3एन2 ही है. हालांकि अभी पुष्टि नहीं है. फिलहाल पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है.

एच1एन1 का ही एक सबटाइप है

इस वायरस में दो प्रोटीन स्ट्रेन एचए और एनए होते हैं. ये वास्तव में एच1एन1 का ही एक सबटाइप है. एच1एन1 स्वाइन फ्लू था जो 2 साल पहले काफी डरावना रूप दिखा चुका है. जिस वायरस के होने की आशंका है वह जीवों के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव के बाद अपनी प्रतिकृति लाखों की तादाद में गढ़ता है यानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक यह आसानी से सफर करता है. इसलिए यह बहुत तेजी से फैलता है और जब इसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है तो यह जानलेवा भी हो जाता है.

8 बार बरपा चुका है कहर

पहली बार एच3एन2 साल 1968 में सामने आया था और हांगकांग में बड़ी तादाद में इसकी चपेट में आकर लोग मरे थे. तब जनवरी से मार्च और जुलाई से अगस्त के बीच यहां लोगों ने इन्फेक्शन की लहर आ गई थी. हांगकांग से यह आगे बढ़कर सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और ताइवान को भी अपनी चपेट में लिया था. इस इन्फ्लूएंजा वायरस की वजह से 19वीं सदी से अब तक 8 बार महामारियों की लहर आ चुकी है. कभी यह स्पेनिश फ्लू के रूप में आता है तो कभी एशियन फ्लू के नाम से.

बॉम्बे फ्लू भी कहते हैं इसे

कहते हैं स्पेनिश फ्लू, जिसे बॉम्बे फ्लू भी कहते हैं, से करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और इसमें से 2 करोड़ से ज्यादा भारतीय थे. वर्ष 2009 में भी इसके चलते अमेरिका में इन्फ्लूएंजा वायरस का यह सबवैरिएंट यानी एच1 एन1 मिला था. वहां से यह दुनिया के 3 दर्जन से ज्यादा देशों में फैल गया और तब इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 11 जून 2009 को महामारी घोषित कर दिया गया था. बहरहाल उस दौर में इससे पूरी दुनिया में करीब पौने 6 लाख लोग काल में समा गए थे.

बहुत सावधान रहने की जरूरत

इंफ्लूएंजा के एक्सपर्ट और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के पूर्व ऑपरेशन हेड डॉ. रणदीप गुलेरिया के मुताबिक एच3एन2 फरवरी, मार्च में बहुत तेजी से फैलता है. इस दौरान बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है. यह इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह वायरस समय के साथ म्यूटेट होता है और उत्तरी गोलार्ध के देशों में आमतौर पर नवंबर में अपनी तीव्रता दिखाता है.

इसे यूं पहचानें

- ✦ जब आप इसकी चपेट में आते हैं तो शुरुआत खांसी से होती है.
- ✦ फिर नाक बहनी शुरू हो जाती है या नाक बंद हो जाती है. - इसके अगले चरण में गले में खरास हो जाती है और भयानक सिरदर्द होने लगता है.
- ✦ फिर शरीर में दर्द के साथ बुखार आता है. कई बार उल्टियां होती हैं. रह-रहकर सांस फूलती है.
- ✦ थकान इतनी होती है कि उठा तक नहीं जाता. कुछ लोगों को इससे बहुत ठंड लगती है और कुछ दस्त का भी शिकार हो जाते हैं.

काबू में करना आसान

डॉ. गुलेरिया कहते हैं इन सब के बावजूद अगर सजग रहें तो इसे बहुत आसानी से काबू में कर सकते हैं क्योंकि यह जानलेवा नहीं है, बशर्ते हम अपनी गलतियों से इसे ऐसा बना न दें.

- ✦ आराम करें लगातार. गुनगुना पानी पिएं. गुनगुने पानी से ही नहाएं.
- ✦ थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते जरूर रहें, भले भूख बिल्कुल न लग रही हो.
- ✦ अगर 48 घंटे के बाद स्थिति बिगड़ने लगे तो डॉक्टर के पास जाएं.
- ✦ अगर थोड़ी कम हो रही हो तो संयम से रहें और कम से 4 दिन तक आराम करते

▲ एस. चौधरी

तीनों फॉर्मेट में शतकों का सूखा खत्म

अंततः 1205 दिनों और 23 टेस्ट मैचों की 41 पारियों के बाद विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में भी सेंचुरी जड़ ही दी. बीते 12 मार्च, 2023 को कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद में टेस्ट क्रिकेट का अपना 28वां और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का 75वां शतक जड़ा. इसके साथ ही वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल शतकों के मामले में अब सिर्फ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से ही पीछे हैं. तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक जमाए हैं. कोहली उनसे अभी 25 शतक पीछे हैं लेकिन पिछले कई वर्षों से रह-रहकर यह सवाल उठता रहा है कि क्या विराट कोहली मास्टर ब्लास्टर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? 3 साल पहले तक तो दुनिया के लगभग सभी विशेषज्ञ यह कहते हुए थकते नहीं थे कि कोहली बहुत आसानी से तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे लेकिन जब लगभग 3 वर्षों तक विराट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी फार्मेट में कोई शतक नहीं बना पाये, लगातार शतक बनाने के लिए जूझते रहे तो क्रिकेट के जानकारों की धीरे-धीरे हिम्मत डोलने लगी. वे यह कहते हुए हिचकिचाने लगे कि विराट तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड आसानी से तोड़ देंगे.

लौट आए ‘विराट’ दिन

दुबई से शुरू हुई शतक की वापसी

हालांकि 8 सितंबर, 2022 को करीब 1200 दिनों बाद दुबई में आयोजित एशिया कप के एक टी-20 मैच में जब विराट ने अफगानिस्तान के विरुद्ध 200 की स्ट्राइक रेट से 12 चौकों और 6 छक्कों से सजी 122 रनों की धुआंधार पारी खेली तो फिर से क्रिकेट के जानकार सचिन और विराट की सदाबहार तुलना करने लगे. शतकों की डगर में दुबई से विराट की जो वापसी हुई, उस वापसी ने धीरे-धीरे लय पकड़ ली. कुछ ही महीनों के भीतर विराट ने एक दिवसीय क्रिकेट में 4 पारियों में से 3 में शतक जड़े. पहले 10 दिसंबर, 2022 को बांग्लादेश के विरुद्ध चट्टोग्राम में खेले गए तीसरे वनडे में विराट कोहली ने 91 गेंदों में 113 रनों की आतिशी पारी खेली. इसमें उन्होंने 11 चौके और 2 छक्के जड़े. इसके बाद 10 जनवरी, 2023 को श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में विराट ने 113 रन बनाये. इसके 5 दिन बाद 15 जनवरी, 2023 को उन्होंने तिरुवनंतपुरम में भी श्रीलंका के विरुद्ध 13 चौकों और 8 छक्कों से सजी 166 रनों की धुआंधार पारी खेली. यह एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की 4 पारियों में उनका तीसरा शतक था. इस तरह 3 वर्षों तक सैकड़े के लिए तरसते रहे विराट अब झमाझम सैकड़ा बरसाने लगे.

टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी का इंतजार

टी-20 और एकदिवसीय क्रिकेट में सैकड़े का सूखा खत्म करने के बाद भी टेस्ट क्रिकेट में उनका यह सूखा खत्म नहीं हो रहा था. 22 दिसंबर, 2022 से बांग्लादेश के विरुद्ध शुरू हुए एकमात्र टेस्ट क्रिकेट की दोनों पारियों में विराट क्रमशः 24 और 1 रन की बना पाये. इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 9 फरवरी, 2023 से शुरू हुई बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट श्रृंखला के नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में वह सिर्फ 12 बन बना पाये. इस टेस्ट श्रृंखला के दूसरे टेस्ट में जरूर वह लय में दिख रहे थे जब दिल्ली में उन्होंने पहली पारी में 44 रन बनाये लेकिन घूमती विकेट पर अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने के बावजूद उनकी यह पारी 44 रन से आगे नहीं गयी. दूसरी पारी में वह सिर्फ 20 रन ही बना सके. 1 मार्च, 2023 से शुरू हुए बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में इंदौर में भी वही हाल रहा. यहां तो कोई भी रन नहीं बना पा रहा था. विराट ने पहली पारी में 22 और दूसरी पारी में 13 रन बनाकर आउट हो गए. अब टेस्ट क्रिकेट में शतकों का सूखा खत्म करने के लिए उनके पास मौजूदा सीरीज का

बदल दी अपनी रणनीति

अहमदाबाद में खेला जाने वाला चौथा टेस्ट ही शेष था. 9 मार्च, 2023 से शुरू हुए इस टेस्ट मैच में पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बैटिंग की और 480 रनों का स्कोर खड़ा किया. भारतीय पारी की शुरुआत भी ठीक रही लेकिन जिस तरह दबाव में हमारे टूटकर बिखरने का इतिहास है, उसके चलते जब 74 रनों पर रोहित शर्मा आउट हो गए और शुभमन गिल तथा चेतेश्वर पुजारा के बीच अगले करीब 40 ओवरों में 100 से भी ज्यादा रनों की हुई साझेदारी के बाद 187 पर भारत के 2 विकेट गिर गए तो न केवल विराट कोहली के लिए टेस्ट मैचों में शतक बनाने का मौजूदा सीरीज में यह आखिरी चांस था बल्कि भारत ऑस्ट्रेलिया के भारी भरकम स्कोर के समानांतर मजबूत स्कोर खड़ा करे, यह सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी थी. कोहली में इसकी योग्यता तो थी लेकिन समय कुछ साथ नहीं दे रहा था. वह 6 महीनों के भीतर क्रिकेट के 2 छोटे फॉर्मेट में 4 सैकड़ा मारने के बाद भी टेस्ट मैचों में विश्वसनीयता से पारी नहीं जमा पा रहे थे. इसे देखते हुए कोहली ने इस टेस्ट में अपनी रणनीति बदल दी. उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ पिच पर रुकने का संकल्प किया. शायद यही वजह थी कि अहमदाबाद में विराट ने अपनी जिंदगी का दूसरा सबसे धीमा शतक बनाया. उन्होंने पहले 100 रन बनाने के दौरान जहां 50 से कम के एवरेज से रन बनाये वहीं इस दौरान सिर्फ 5 चौके लगाये. हालांकि दोहरे शतक के बिल्कुल करीब पहुंचकर जब वह आउट हुए तब तक उनकी पारी में 15 चौके हो चुके थे और 186 रन बनाने के लिए उन्होंने 364 गेंदें खेलकर 51.09 की स्ट्राइक रेट भी हासिल कर चुके थे. इस तरह अंततः टेस्ट क्रिकेट का 28वां और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का 75वां शतक भी उन्होंने बना दिया.

6 माह में फिर आसमान पर

इस तरह सितंबर से मार्च के बीच यानी 6 महीने के भीतर उन्होंने 5 सेंचुरी लगाकर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सेंचुरी के सूखे को खत्म कर दिया. किंग कोहली की इस सेंचुरी ने जहां उनकी क्लास और उनकी रेपुटेशन को फिर से स्थापित किया है वहीं विशेषज्ञों ने यह भी जोर देकर कहा कि फॉर्म में न होने के बावजूद भी अगर कोहली तय कर लें तो वे पिच पर टिककर कभी भी सैकड़ा मार सकते हैं.

तोड़ देंगे सचिन का रिकॉर्ड...

अहमदाबाद में शतक बनाने के बाद विराट के फैंस उन्हें अपनी चाहत के शिखर पर तो बैठाया ही है, विशेषज्ञ फिर से कहने लगे हैं कि विराट जल्द ही क्रिकेट के भगवान के 100 सैकड़ों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे. हरभजन सिंह ने यह संख्या भी बता दी. उनके मुताबिक विराट अगले 4 वर्षों में 50 शतक और बनाएंगे. इस तरह वह जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर अपना बल्ला खूंटी पर टांगेंगे तो उनके आगे तब 125 सेंचुरी दर्ज होगी.

▲ साशा

ऐसे सुधारें सिबिल स्कोर

यह बिगड़ा है तो बैंक नहीं देते लोन

यह तो हम सब जानते हैं कि अगर हमारा सिबिल स्कोर खराब हो तो हमें बैंक लोन नहीं देते. लोन देते भी हैं तो हमसे ज्यादा ब्याज दर की मांग करते हैं. हमारा क्रेडिट कार्ड नहीं बनता और बहुत सारी वित्तीय योजनाओं का लाभ पाने से हम वंचित कर दिये जाते हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की तारीख में सिबिल स्कोर का सही होना कितना जरूरी है. दरअसल क्रेडिट स्कोर या जिसे सिबिल स्कोर कहते हैं वह 300 से 900 अंकों के बीच की एक संख्या होती है. यह वास्तव में हमारी भुगतान हैसियत होती है जो देश के क्रेडिट ब्यूरो द्वारा निर्धारित की जाती है. यह अप्रत्यक्ष तौर पर बैंक व वित्तीय संस्थानों के लिए ही जारी होती है कि वे हमें उधार देने के पहले हमारी भुगतान साख को जान लें क्योंकि हमारा सिबिल स्कोर हमारे लिए गए कर्जों के भुगतान की प्रवृत्ति पर ही आधारित होता है. मसलन अगर हमने कोई कर्ज लिया है और हम योजना के मुताबिक सही समय पर उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा क्रेडिट स्कोर कम होगा. दूसरे शब्दों में हम कर्ज पाने के मामले में नकारात्मक समझे जाएंगे.

भुगतान आचरण की हिस्ट्री

क्रेडिट रिपोर्ट में हमारे भुगतान आचरण की हिस्ट्री छिपी होती है. यही हमारी साख का प्रतिनिधित्व करती है. अगर हमारा क्रेडिट स्कोर कम है तो हमें कोई भी बैंकिंग संस्थान कर्ज देते समय असमंजस में रहेगा कि दिया गया कर्ज कहीं फंस न जाए. इसलिए बैंक कम क्रेडिट स्कोर वाले व्यक्ति को लोन देने से हिचकिचाते हैं. अगर लोन दे भी दें तो बहुत सारी चीजें देखते हैं और ऐसे लोगों से ब्याज दर भी ज्यादा वसूलतते हैं. बैंकों से सर्वश्रेष्ठ ब्याज दर हासिल करने के लिए बढ़िया सिबिल स्कोर होना जरूरी है. 750 और इससे अधिक के सिविल स्कोर को ही लोन देने के लिए ठीक-ठाक स्कोर माना जाता है. अगर आपका सिविल स्कोर 750 से कम है तो आप नकारात्मक स्थिति में हैं. लोन देने वाले संगठन आपके लोन के आवेदन को रद्द कर सकते हैं या फिर वे कहेंगे कि अपना सिबिल स्कोर सुधार लो.

समयसीमा में करें पेमेंट

सवाल है सिबिल स्कोर कैसे सुधारा जाए? हालांकि इससे पहले यह समझना जरूरी है कि क्रेडिट स्कोर आखिर कम कैसे हो जाता है? अगर आप ने लोन ले रखा है या आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उनका भुगतान तय समय पर हर हाल में कर दें. अगर आप भुगतान समयसीमा के बाद करते हैं तो इसका असर आपके सिबिल स्कोर पर पड़ता है. फिर चाहे भले आप पूरा भुगतान करते हों. अगर आप समय पर भुगतान करते हैं तो आपके सिबिल स्कोर में वृद्धि होती है. सबसे ज्यादा सिबिल स्कोर कम तब होता है जब हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हों और आमतौर पर उसकी पूरी लिमिट का इस्तेमाल कर लेते हों. इससे सिबिल कम या निगेटिव होता है.

क्रेडिट कार्ड में बैलेंस बनाये रखें

हमारा क्रेडिट उपयोग भी हमारी क्रेडिट हैसियत को बढ़ाता या घटाता है. यानी इससे भी हमारा सिबिल स्कोर प्रभावित होता है. तो, न सिर्फ देर से भुगतान करने से बचें बल्कि क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट का कभी इस्तेमाल न करें. एक अच्छे उपभोक्ता के लिए जरूरी है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड में बैलेंस बनाये रखें. यही नहीं, क्रेडिट स्कोर तब भी नीचे जाता है जब एक समय पर आपके कई लोन चल रहे होते हैं. अपने क्रेडिट बैलेंस को बनाये रखने के लिए हमें अपनी क्रेडिट कमियों की भी जांच करनी चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सारे लोन समय पर चुका देते हैं लेकिन फिर भी हमारा क्रेडिट स्कोर सही नहीं होता. इसकी वजह कुछ लापवाहियां भी होती हैं जो हमारी भी हो सकती हैं और हमारे बैंक की भी.

अदायगी के बाद चेक जरूर करें

मान लीजिए आपका अच्छा क्रेडिट रिकॉर्ड है और आप ने सब लोन सही समय पर चुका दिया है. यही नहीं, इसे आपकी तरफ से बंद भी कर दिया गया है लेकिन यह प्रशासनिक कमी के कारण आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में एक्टिव दिखाई देती है. इससे भी क्रेडिट स्कोर प्रभावित होगा. इसलिए अपने लोन का पूरा भुगतान करने के बाद इसे चेक करना भी जरूरी है कि कहीं ऐसा न हो कि गैर जिम्मेदारी के चलते बैंक ने आपका लोन बंद ही न किया हो? अच्छे क्रेडिट बैंलेंस बनाये रखने के लिए क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ऑटो लोन और होम लोन में संतुलन होना चाहिए. जो लोग ज्यादा सिक्योर लोन लेते हैं, बैंक उन्हें ही आसानी से लोन देना पसंद करते हैं. क्रेडिट और पर्सनल लोन लेने वालों को बैंक लोन देना पसंद नहीं करते.

▲ विवेक कुमार

एक नज़र

अफगानिस्तान में आईएस के कई आतंकवादी मारे

काबुल, (एजेंसी)। अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों ने उत्तरी बल्ख प्रांत में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर छापेमारी कर कई आतंकवादियों को मार गिराया है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रशासन के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने शनिवार को यह जानकारी दी। अभियान में मारे गए आईएस आतंकवादियों की संख्या नहीं बताई। इसमें एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया।

ब्राजील में हेलीकॉप्टर क्रैश चार लोगों की गई जान

साओ पाउलो, (एजेंसी)। ब्राजील के साओ पाउलो में एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार चार लोगों की मौत हो गई। अग्निशमन विभाग के ट्वीट में हादसा शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बर्रा फंडा के पास इससे नौ वाहन प्रभावित हुए हैं। ब्राजीलियाई हेलीकॉप्टर पायलट एसोसिएशन में 411 निजी पंजीकृत हेलीकॉप्टर हैं और वर्ष 2021 डेटा के मुताबिक ये प्रति दिन 2,200 उड़ान भरते हैं।

कश्मीर में सड़क दुर्घटना बिहार के चार मजदूर मरे

श्रीनगर, (एजेंसी)। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा उप जिले में शनिवार सुबह बस के पलट जाने से बिहार के चार मजदूरों की मौत हो गई और करीब 32 लोग घायल हो गए। मृतकों के पहचान कैसर आलम, सलीम, नसीरुद्दीन और राजकुमार दास (सभी बिहार निवासी) के रूप में की गई है। सभी घायल अलग-अलग अस्पताल में भर्ती हैं इनमें से कुछ गंभीर हैं।

मोर्टार विस्फोट होने से दो बच्चों की मौत, दो घायल

काबुल, (एजेंसी)। अफगानिस्तान के पूर्वी लोगर प्रांत में पिछले युद्धों से बची मोर्टार माइन में विस्फोट होने से दो बच्चों की मौत और दो अन्य घायल हो गए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक लोगार प्रांत की राजधानी पुल-ए-आलम शहर के अलतामोर में शुक्रवार शाम बच्चों के एक समूह को खिलौने जैसा उपकरण मिला और वह उससे खेलने लगे। इस बीच उपकरण में अचानक विस्फोट हो गया।

मलावी फ्रेडी चक्रवात से 5 लाख लोग प्रभावित: संरा

संयुक्त राष्ट्र, (एजेंसी)। पूर्वी अफ्रीकी देश मलावी में फ्रेडी चक्रवात से कम से कम 326 लोगों सहित 500,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मलावी स्थिति मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएच) ने कहा कि सरकार ने अकेले गुरुवार को राहत एवं अभियान के दौरान 442 लोगों को बचाए जाने की रिपोर्ट दी है। वहीं, 180,000 से अधिक लोग बेघर हो गए।

बागेश्वर आत्महत्या: मिला छह पेज का सुसाइड नोट

बागेश्वर/नैनीताल, (एजेंसी)। उत्तराखंड के बागेश्वर में चार लोगों के शव मिलने के मामले में सल्फास के अलावा पुलिस को मौके से छह पेज का एक सोसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए सामूहिक आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाने की बात कही है। बागेश्वर पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार वर्मा ने शनिवार को इसका खुलासा किया।

लेफ्टिनेंट कर्नल रेड्डी की हैदराबाद में अंत्येष्टि

हैदराबाद, (एजेंसी)। लेफ्टिनेंट कर्नल वी विजय भानु रेड्डी (41) का पार्थिव शरीर बेगमपेट वायु सेना स्टेशन पहुंचा। बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल रेड्डी 16 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में एक ऑपरेशनल सॉर्टी के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल रेड्डी को पुष्पांजलि पिता वेंकटेश ने अर्पित की। पार्थिव शरीर को मलकजगिरी स्थित उनके निवास स्थान से अंतिम संस्कार के लिए यदाद्री भुवनगिरि जिले के बोम्मलाराराम गांव में होम स्टेशन ले जाया जाना था, जहां शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया।

इतिहास

- **1279:** मंगोलों ने चीन के सांग वंश का अंत किया।
- **1775:** पोलैंड और प्रशिया ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- **1861:** पहला तारानाकी युद्ध न्यूजीलैंड में समाप्त किया गया।
- **1866:** मोनार्क लीवरपुल में घुसपैठियों से भरा जहाज डूबने से 738 की मौत।
- **1944 :** आजाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
- **1953:** पहली बार एकेडमी अवार्ड का प्रसारण टेलीविजन पर हुआ।
- **1982:** अर्जेंटीना ने दक्षिणी जॉर्जिया में झंडा फहराया।
- **1998:** अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने।
- **2008:** पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सबरजीत की फांसी 30 अप्रैल, 2008 तक रोकी।

पुतिन 123 देशों में हो सकते हैं गिरफ्तार, रूस ने अरेस्ट वारंट को बताया टॉयलेट पेपर

नई दिल्ली,(एजेंसी)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। ये वारंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) ने जारी किया है। आईसीसी ने पुतिन के अलावा रूस की चिल्ड्रन राइट्स कमिश्नर मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया है । पुतिन व मारिया के खिलाफ ये वारंट वॉर क्राइम के जुर्म में जारी किया गया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इस वारंट की तुलना टॉयलेट पेपर से कर दी। वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अरेस्ट वारंट को शुरुआती कदम बताया है। पुतिन पर लगे वॉर क्राइम आरोपों की जांच कर रहे आईसीसी के प्रॉसिक्यूटर करीम खान ने बताया कि अगर पुतिन अगर आईसीसी के 123 सदस्य देशों में से किसी भी देश में जाते हैं, तो उन्हें वहां गिरफ्तार किया जा सकता है।

इधर यूक्रेन पर हमला तेज

कीव, (एजेंसी)। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के बाल अधिकार आयुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के इस फैसले के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी वायुसेना ने शनिवार को कहा कि उसके देश पर शुक्रवार की रात 16 रूसी ड्रोन ने हमला किया। टेलीग्राम पर वायुसेना कमान ने लिखा कि 16 में से 11 ड्रोन को केंद्रीय, पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में मार गिराया गया। जिन इलाकों को निशाना बनया गया उनमें कीव, पश्चिमी ल्वीव प्रांत शामिल हैं। कीव शहर प्रशासन के प्रमुख सेर्ही पोपको ने कहा कि यूक्रेनी वायुसेना ने यूक्रेन की राजधानी की ओर जाने वाले सभी ड्रोनों को मार गिराया। ल्वीव के क्षेत्रीय गवर्नर मैक्सिम कोजित्स्की ने कहा कि 6 में से 3 ड्रोन को मार गिराया गया, जबकि अन्य तीन ने पोलैंड की सीमा से लगे जिले को निशाना बनाया।

डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जताई गिरफ्तारी की आशंका

न्यूयॉर्क, (एजेंसी)। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने कहा कि न्यूयॉर्क पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पर तुली है। डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें मंगलवार को गिरफ्तार किया जाएगा। मैनहट्टन के अभियोजक हश मनी मामले में उन्हें आरोपित करने वाले हैं।

2016 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर किए गए कथित गुप्त भुगतान को लेकर उन पर आरोप तय किए जाने हैं।इन संभावनाओं के मद्देनजर अधिरकारी व्यापक सुरक्षा इंतजाम करने की कवायद में जुट गए हैं। मामले में अगर ट्रंप को अभ्यारोपित किया जाता है, तो यह अमेरिकी इतिहास में पहली बार होगा, जब किसी पूर्व राष्ट्रपति पर किसी मामले में आरोप लगाए जाएंगे।

राष्ट्रपति मुर्मु कन्याकुमारी और लक्षद्वीप के दौरे पर

चेन्नई, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में संत कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा स्थल और विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा किया। इससे पूर्व श्रीमती मुर्मु भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर से तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी पहुंचीं।

श्रीमती मुर्मु ने विवेकानंद रॉक और विवेकानंद केंद्र का भी भ्रमण किया। इन पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के यहां आने की उम्मीद रहती है। यहां से लक्षद्वीप के लिए रवाना हो गईं। श्रीमती मुर्मु 16 से 21 मार्च तक केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के दौरे पर हैं।

काशी विश्वनाथ के दर पर सौ बार मत्था टेकने वाले पहले सीएम बने योगी आदित्यनाथ

वाराणसी, (ब्यूरो)। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही वह ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं जिन्होने बाबा विश्वनाथ के दरबार में 100वीं बार हाजिरी लगाई है। वर्ष 2017 में पहली बार प्रदेश की सत्ता संभालने वाले श्री योगी जब भी काशी आते हैं, अमूमन हर बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी जरूर लगाते हैं और षोडषोपचार विधि से दर्शन पूजन कर लोक कल्याण की कामना करते हैं। वर्ष 2017 से अभी तक अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी आदित्यनाथ 100 बार बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं।

सीएम योगी शुक्रवार को 113वीं बार वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर आये। दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया है, जिसने नया कीर्तिमान बनाया है। श्री योगी महीने में एक बार या कभी-कभी दो बार काशी की यात्रा जरूर करते हैं। अपने हर दौरे में मुख्यमंत्री विकास कार्यो की समीक्षा और स्थलीय निरीक्षण करते हैं। जिसका परिणाम वाराणसी के चतुर्दिक विकास के रूप में दिखता है। अगर छह साल के हिसाब से देखें तो योगी औसतन हर 21 दिन पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं। योगी आदित्यनाथ पहले और दूसरे कार्यकाल के 72 महीनों में करीब 100 बार बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचने वाले पहले सीएम बन गये हैं। पहली बार उप्र की कमान संभालने के बाद योगी 2017 से मार्च 2022 तक कुल 74 बार भगवान विशेश्वर से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे।

गुजरात के गांधीनगर में 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन का आयोजन

देश के डेयरी विकास में आईडीए का योगदान महत्वपूर्ण: गृहमंत्री शाह

गांधीनगर, (एजेंसी) केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में कहा कि देश में डेयरी क्षेत्र के विकास में इंडियन डेयरी एसोसिएशन (आईडीए) का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

श्री शाह शनिवार को इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा आयोजित 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कहा कि दुनिया के लिए डेयरी एक व्यापार है, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश में ये रोजगार का साधन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का विकल्प, कुपोषण की समस्याओं का समाधान प्रदान करने वाला और महिला सशक्तिकरण की संभावनाओं वाला क्षेत्र है। भारत की आजादी से अब तक के डेयरी उद्योग के विकास को देखें तो इन सभी पहलुओं को हमारे डेयरी सेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से देश के विकास के साथ जोड़ने के लिए काम किया है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इसमें कोऑपरेटिव डेयरी का योगदान रहा है, जिन्होंने किसानों की समृद्धि के लिए काम किया है। कोऑपरेटिव डेयरी ने देश की गरीब कृषक महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी के 75वें वर्ष में सहकार से समृद्धि मंत्र को सिद्ध करने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया।

नौ करोड़ ग्रामीण परिवार के लोग डेयरी क्षेत्र से जुड़े

इस दौरान श्री शाह ने कहा कि डेयरी हमारी अर्थव्यवस्था का मजबूत हिस्सा है और रोजगार की दृष्टि से देखें तो नौ करोड़ ग्रामीण परिवारों के लगभग 45 करोड़ लोग, विशेषकर सीमांत किसान और महिलाएं सीधे डेयरी क्षेत्र से जुड़े हैं। श्री शाह ने इंडियन डेयरी एसोसिएशन (आईडीए) द्वारा आयोजित 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में कहा कि हमारे डेयरी और पशुपालन क्षेत्र का देश के जीडीपी में 4.5 प्रतिशत योगदान है और कृषि क्षेत्र में डेयरी क्षेत्र का योगदान 24 प्रतिशत है, जो 10 लाख करोड़ रुपए के साथ विश्व में सबसे अधिक है। डेयरी हमारी अर्थव्यवस्था का मजबूत हिस्सा है और रोजगार की दृष्टि से देखें तो नौ करोड़ ग्रामीण परिवारों के लगभग 45 करोड़ लोग विशेषकर सीमांत किसान और महिलाएं आज सीधे डेयरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पिछले एक दशक में 6.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से हमारे डेयरी क्षेत्र ने प्रगति की है।

प्रवासी सम्मेलन में पहुंचे पुनियां

जयपुर, (एजेंसी) भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां शनिवार को दुबई प्रवास पर हैं और वहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भाजपा प्रवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजू मंगोड़ीवाला ने बताया कि डॉ. पूनियां विभिन्न प्रवासी भारतीय एवं राजस्थानी संगठनों के आमंत्रण पर सुबह दुबई पहुंचे।

डॉ. पूनियां दुबई में कई कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद लेबर कैंप का निरीक्षण करेंगे।

जिलों में रोजगार मेले कल लगेंगे

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सरकार ने देश भर के 200 से अधिक जिलों में 20 मार्च को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजित किया जाएगा जिसमें बड़े पैमाने पर बेरोजगार युवकों का रोजगार भी मिलेगा।

पीएम नरेंद्र मोदी के कौशल भारत मिशन के तहत भारत के युवाओं के लिए कैरियर के अवसरों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के तहत आवश्यकता पूरी करने वाले लोगों का चयन कर सकते हैं।

कोल्ड स्टोर का मालिक गिरफ्तार

मुरादाबाद, (एजेंसी) उत्तर प्रदेश के संभल में कोल्ड स्टोर हादसे में पुलिस ने शनिवार रात कोल्ड स्टोर स्वामी रोहित अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल को गिरफ्तार किया है।

मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक अंकुर अग्रवाल और रोहित अग्रवाल को शुक्रवार देर शाम उत्तराखंड के हल्द्वानी से गिरफ्तार किया गया है। दुर्घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य रोक दिया गया है। इसके बाद मलबे को हटाने का काम जारी है। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि दस को बचा लिया गया है जिनमें चार लोग उपचाराधीन हैं। पुलिस उपमहानिरीक्षक शलभ माथुर ने बताया कि हादसे में गैर इरादतन हत्या के दर्ज मामले में कोल्ड स्टोर स्वामी अंकुर अग्रवाल तथा रोहित अग्रवाल को हल्द्वानी उत्तराखंड से कल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मालिकों के खिलाफ चन्दौसी थाने में गैर इरादतन हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, उन्हें गिरफ्तार किया है।

ब्रिटेन में हड़तालरत जूडॉ सरकार से बात को तैयार

लंदन, (एजेंसी)। ब्रिटेन के जूनियर डॉक्टरों के संगठन ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन (बीएमए) और सरकार वेतन को लेकर तीन दिनों तक चली हड़ताल के बाद बातचीत को सहमत हो गए हैं। इस हड़ताल के कारण अस्पतालों में हजारों मरीजों के अपॉइंटमेंट और सर्जरी रद्द करनी पड़ी थी।

एजेंडे के समान प्रस्ताव किया स्वीकार

स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल विभाग ने स्काई न्यूज ब्रॉडकास्टर के हवाले से कहा कि हमें खुशी है कि बीएमए ने यूनियनों को बदलने के एजेंडे के समान शर्तों के आधार पर वार्ता में प्रवेश करने के हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वॉकआउट के कारण 1,75,000 से अधिक नियुक्तियों और प्रक्रियाओं को इस सप्ताह रद्द किया।

बिजली हड़ताल से यूपी में हाहाकार सरकार-कर्मियों में नहीं बनी बात

लखनऊ, (एजेंसी)। बिजली हड़ताल के चलते यूपी में पूरब से पश्चिम तक हाहाकार मचा हुआ है। समझाने-बुझाने और सख्ती के बावजूद सरकार और हड़ताली कर्मचारियों के बीच बात नहीं बनी। इस बीच अलग-अलग जिलों में सैकड़ों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है।

बिजली सप्लाई बाधित करने वाले हजारों कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की गई है। सरकार बड़े ऐक्शन की तैयारी में है। उधर, कर्मचारी भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने हड़ताल करने व अराजकता फैलाने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए हड़ताल करने वाले 22 कर्मचारियों पर एस्मा के तहत कार्यवाही अभी तक 29 कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए है 06 सस्पेंड कर उनको लखनऊ के बाहर भेजने के दिए निर्देश हड़ताल में शामिल होने और कार्य न करने पर 1332 संविदा कार्मिक बर्खास्त 4 घंटे की मौहलत और कार्य पर वापस नहीं वाले हजारों बर्खास्त होंगे।

फ्रांस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल

पेरिस, (एजेंसी)। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्ने के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अब तक दो अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किए जा चुके हैं। सुश्री बोर्ने पर विवादास्पद पेंशन सुधार विधेयक को नेशनल एसेंबली में मतदान के बिना पारित कराने पर विवश करने का आरोप है। पहला बहुदलीय प्रस्ताव मध्यमार्गी विपक्षी समूह एलआईओटी ने दायर किया था।

पेंशन सुधार के मुद्दे पर 91 विपक्षी एकजुट

इसमें विभिन्न दलों के 91 विपक्षी द्वारा सह-हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं दूसरा प्रस्ताव द फार-राइट नेशनल रैली पार्टी द्वारा पेश किया गया , जिसके नेशनल असेंबली में 88 प्रतिनिधि हैं। इस पार्टी के सदस्यों का तर्क है कि पेंशन नीति में बदलाव अनुचित और अनावश्यक है। सुश्री बोर्न ने गुरुवार को देश के संविधान के एक लेख को उल्लेख किया जो सरकार को नेशनल असेंबली में वोट के बिना विवादास्पद पेंशन सुधार विधेयक को पारित करने की अनुमति देता है।

दो नए एयरक्राफ्ट करियर होंगे नेवी में शामिल, चीन को देंगे टक्कर

नई दिल्ली,(एजेंसी)। नौसेना आईएनएस विक्रांत की तरह एक नया एयरक्राफ्ट करियर बनाने जा रही है, जो ठीक उसी आकार, वजन और डिस्प्लेसमेंट का होगा। लेकिन ज्यादा आधुनिक, ताकतवर और घातक होगा। अभी भारत के पास दो विमानवाहक युद्धपोत हैं।

पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी भारत की धाक के साथ ताकत

पहला आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस दोनों ही युद्धपोत दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ विमानवाहक युद्धपोतों में शामिल हैं। विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट करियर बनने से हम चीन की नौसेना की बराबरी कर लेंगे। उसके पास भी तीन एयरक्राफ्ट करियर हैं। पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। आईएनएस जैसा एक और एयरक्राफ्ट करियर भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना बढ़ा देगी। दक्षिण एशिया और हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में पावर बैलेंस बनाएगी।

पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर को बनने में 13 साल लग गए थे लेकिन नया बनने में इतना समय नहीं लगेगा यह आधे समय भी बन सकता है। साथ ही इसे ज्यादा घातक, आधुनिक और भरोसेमंद बनाया जा सकेगा। अगर विक्रांत जैसा भी एक करियर बनकर तैयार हो जाता है तो भारत की धाक पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी। विक्रांत में बराक-8 और ब्रह्मोस मिसाइल लगाए जाने की खबर है। इसके अलावा कोस्टल बेस्ड एके-603 गन और ओटोब्रेडा कैनन लगे हैं।

दुनिया के सबसे छोटे बॉडी बिल्डर ने रचाई शादी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दुनिया के सबसे छोटे बॉडी बिल्डर प्रतीक विट्ठल मोहिते ने शादी रचा ली। 3 फीट, 4 इंच लंबे प्रतीक की पार्टनर जया 4 फीट 2 इंच लंबी हैं। प्रतीक के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब भी है। उनके नाम यह रिकॉर्ड दुनिया का सबसे छोटा बॉडी बिल्डर कॉम्पटीटिव होने के लिए दर्ज है। उन्हें यह खिताब साल 2021 में मिला था। प्रतीक ने अपने सपनों की लड़की से इस महीने की शुरुआत में शादी रचाई। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य और कई दोस्त भी मौजूद रहे। 28 साल का यह बॉडी बिल्डर अपनी 22 साल की पार्टनर जया से चार साल पहले मिला था। बाद में दोनों की सगाई हो गई थी।

बता दें कि प्रतीक एक इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर भी हैं। यहां पर उनके दो लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। प्रतीक अपने फिटनेस वीडियोज पोस्ट करते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट कीं, यहां पर बधाई देने वाले कमेंट्स की भरमार हो गई। प्रतीक के अकाउंट पर हल्दी और बारात समारोह के तमाम वीडियो और फोटो भरे पड़े हैं।

ससुराल दूर थी, दुल्हन ने 7 घंटे में पुलिस बुलाकर तोड़ दी शादी

वहीं उप्र में एक लड़की ने घरवालों की मर्जी से कोर्ट मैरिज और फिर अरेंज मैरिज की. पूरे रीति-रिवाज से दुल्हन बनकर दूल्हे संग विदा हुई। बनारस (उत्तर प्रदेश) की रहने वाली वैष्णवी की शादी बीकानेर (राजस्थान) के रवि से तय हुई थी। रवि अपनी बारात लेकर गुरुवार को बीकानेर से आया. ज्यादा खर्च न हो, इसलिए रवि और वैष्णवी की बनारस में कोर्ट मैरिज और फिर अरेंज मैरिज हुई। कार में सवार नई-नवेली दुल्हन ने करीब 400 किमी का सफर भी तय कर लिया, लेकिन जब उसे पता चला कि ससुराल अभी भी 900 किमी और दूर है तो उसने गाड़ी रुकने का इंतजार किया। जब चाय नाश्ते के लिए दूल्हा समेत उसके घरवाले उतरे तो दुल्हन पास खड़े पुलिसकर्मियों के पास जा पहुंची और रोते हुए अपनी शादी तोड़ने की जिद पर अड़ गई। इसके बाद पुलिस ने थाने से महिला पुलिसकर्मी बुलाकर दुल्हन को वापस मायके भेज दिया और उधर दूल्हा बेरंग लौटा। लड़के वालों ने कहा कि लड़की वाले सब जानते थे।

खतरा घटा **अंतरराष्ट्रीय चिंता के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में खत्म हो सकता है कोविड-19**

कोविड 2023 में महज़ मौसमी फ्लू रह जाएगा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोविड-19 से दुनियाभर में अब तक 70 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अदनोम घेबरेसस ने शुक्रवार को जिनेवा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हम यह कहने में सक्षम होंगे कि अंतरराष्ट्रीय चिंता के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में कोविड-19 खत्म हो सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि कोविड-19 महामारी इस वर्ष स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रह जाएगी। टेड्रोस ने कहा कि वायरस अधिक संक्रामक हो सकता है लेकिन गंभीर बीमारी का कारण नहीं बनता है। 11 मार्च, 2020 को कोविड-19 को महामारी के रूप में चिह्नित किया गया था।धीरे-धीरे इसका खतरा मौसमी फ्लू की तरह रह जाएगा। मुझे लगता है कि हम उस बिदु पर आ रहे हैं, जहां हम कोविड-19 को उसी तरह से देख सकते हैं जैसे हम मौसमी इन्फ्लुएंजा को देखते हैं।÷ उन्होंने कहा कि कोविड मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बना रहेगा।

देश के 76 नमूनों में कोविड का नया प्रकार- देश में कोविड-19 के 76 नमूनों में वायरस का नया प्रकार एक्सबीबी1.16 पाया गया है। यह देश में कोविड-19 के मामलों में हालिया बढोतरी की वजह हो सकता है। इंसाकाग के आंकड़ों के अनुसार, कोरोना वायरस का यह नया स्वरूप जिन नमूनों में मिला है, उनमें से 30 कर्नाटक, 29 महाराष्ट्र, सात पुडुचेरी, पांच दिल्ली, दो तेलंगाना, एक-एक नमूने गुजरात-हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं।

चमगादड़ नहीं, कुत्ते से दुनिया में फैला कोरोना

बीजिंग, (एजेंसी)। चीन में कोविड-19 के पहले मामले की पहचान की गई थी, उस बाजार से मनुष्य के नजदीक से मिले अनुवांशिक सैंपल से पता चला है कि रैकून कुत्ते का डीएनए वायरस के साथ मिश्रित हुआ। इससे इस सिद्धांत को बल मिला है कि वायरस की उत्पत्ति प्रयोगशाला से नहीं बल्कि पशुओं से हुई थी। यह जानकारी अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस ने कहा कि ये आंकड़े इस बात का निश्चित जवाब नहीं देते कि महामारी की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन उस जवाब के करीब ले जाने के लिए प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक: डोटासरा ने कहा- जनता के बीच मोदी सरकार की विफलताओं को करें उजागर

सीएम की नसीहत, जनता के बीच कुशल नेता की छवि बनाएँ

हिलव्यू समाचार

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत सोमवार को पीसीसी में पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्षों की बैठक में कहा कि सभी जिला व ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां अपने-अपने क्षेत्र में आम जनता के कार्यों का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजेंगे तो सरकार उन प्रस्तावों के आधार पर विकास के काम करेगी। गहलोत ने पार्टी नेताओं को नसीहत दी हैं कि जनता के बीच व्यवहार कुशल नेता की छवि बनाएं तथा अपने-अपने क्षेत्रों में आम लोगों की सहायता करने एवं सुख-दुःख में शामिल होने में कोई कसर ना छोड़ें। उन्होंने कहा कि पार्टी के कारण उनकी पहचान बनी है तथा यही तथ्य सभी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं पर लागू होते हैं। इसलिए सभी कांग्रेसजनों को पार्टी के हित में एवं पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना-अपना योगदान देना चाहिए।

अधिवेशन में पारित प्रस्तावों पर की चर्चा

प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने बैठक को लेकर कहा कि हमारे जो नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, बोर्ड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उसकी समीक्षा की गई है। जो नए ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, उन्हें हिदायत दी गई है, जल्द से जल्द कार्यकारिणी बनेगी। उन्होंने कहा कि जो अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किए गए थे कि बूथ इकाई, ग्राम पंचायत इकाई, मंडल कार्यकारिणी और संगठन के जितने भी रिक्त पद हैं, उनको भरना है। उसके लिए भी चर्चा की गई है। उनके स्तर पर भी काम होना है, उस पर भी अपेक्षा की गई है, जो हमारे स्तर पर होना है उस पर भी विचार विमर्श किया गया है। जल्द ही हाईकमान को हमारे सुझाव दे दिए जाएंगे और जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, उन्हें लाभ मिले जो मोदी सरकार की गलत नीतियां हैं, उन्होंने जो महंगाई बढ़ा रखी है, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अडाणी घोटाला हुआ है, इन सब चीजों को जनता को बताएंगे, गांव में, बूथ-बूथ पर बताएंगे, घर-घर जाकर बताएंगे।

चुनाव को लेकर मंथन: रंधावा

बैठक को लेकर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि हमने बैठक में चर्चा की, कि सरकार की नीतियों को, उसके प्रचार को कैसे आगे बढ़ाना है, हमारे सीएम अशोक गहलोत काफी अनुभवी राजनेता हैं, सबसे कम उम्र में वे मंत्री बने, हमसे बड़े भी हैं, पहले इंदिरा गांधी के समय में सबसे छोटी उम्र के मंत्री थे, तीन बार चीफ मिनिस्टर बने तीन बार ऑर्गेनाइजेशन में रहे। कांग्रेस को दिसंबर में आने वाले चुनाव में कैसे लेकर जाना है, उसमें क्या-क्या कार्य करेंगे उस पर चर्चा की गई।

वास्तुविद् पं. सतीश शर्मा ने इंजीनियरों को दिए वास्तु के गुर

अब प्रदेश में वास्तुशास्त्र के अनुसार बनेंगे आवासन मंडल के भवन

हिलव्यू समाचार

जयपुर। आवासन मंडल की ओर से आगामी समय में वास्तु शास्त्र के अनुसार आवासीय और व्यवसायिक निर्माण कार्य किए जाएंगे। राजस्थान आवासन मंडल मुख्यालय में मंगलवार को 'वास्तु शास्त्रः आवासन एवं नियोजन में उपादेयता' विषय पर राज्य स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यहां आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने कहा कि मंडल गुणवत्ता के साथ आमजन का भरोसा और विश्वास भी जीतेगा। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप का उद्देश्य वास्तु से जुड़ी भ्रांतियां दूर कर वैज्ञानिक व तार्किक बातों की स्वीकार्यता बढ़ाना है। मंडल ने सदैव आमजन की भावनाओं और बदलते समय और मांग का ख्याल रखते हुए भवनों का निर्माण किया है। गौरतलब है कि आम जनता वास्तु शास्त्र के अनुसार बने आवासों में अधिक दिलचस्पी दिखाती है। इसे देखकर यह फैसला लिया गया। वर्कशॉप में ज्योतिषाचार्य सतीश शर्मा ने मंडल के तकनीकी इंजीनियरों तथा अधिकारियों को पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के जरिए वास्तु के गुर दिए।

> आज के दौर में आमजन की प्राथमिकता वास्तु आधारित भवनों को खरीदने की रहती है, आमजन की इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारियों के साथ वास्तु शास्त्र पर गहन मंथन किया है ताकि गुणवत्ता के साथ आमजन का वास्तु सम्मत आवास भी उपलब्ध कराए जा सकें।
>
> **पवन अरोड़ा,** आवासन आयुक्त

इंसानों ने किया दिशाओं का निर्धारण: शर्मा

वास्तुविद् और ज्योतिषाचार्य सतीश शर्मा ने दिशा संबंधी वास्तु पर जोर देते हुए कहा कि दिशाएं भगवान द्वारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई है। दिशाओं का निर्धारण इंसानों ने किया है, ऐसे में किसी खास दिशा को दोष वास्तु नहीं देता। वास्तु पूरी तरह सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा पर कार्य करता है। सही मायनों में वह भवन पूरी तरह सफल होता है, जहां पंचतत्व को पर्याप्त और सही स्थान मिल सके। मंडल ने निर्माण में वास्तु शास्त्र का ध्यान रखने की कार्य योजना बनाई है।

घर बैठे लोगों को रोजगार दे रहा है खादी ग्रामोद्योग

40 अगरबत्ती पैडल चालित मशीन 100 फुटवियर टूल किट वितरित

हिलव्यू समाचार

जयपुर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 40 अगरबत्ती पैडल चालित मशीन तथा 100 फुटवियर टूल किट के वितरण किए गए। इसमें 50 किट ग्राम सावरदा, तहसील मौजमाबाद तथा 50 किट चौमूं जिला जयपुर में लाभार्थियों को प्रशिक्षण देकर वितरित की गई। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत रुपए 100 करोड़ की मार्जिन मनी ऑनलाइन माध्यम से बैंकों को वितरित की गई। इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने अपने वर्चुवल संबोधन में कहा कि खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से घर बैठे लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने संस्थाओं से आग्रह किया कि संस्थाओं को खादी कार्यक्रम के साथ-साथ ग्रामोद्योग का कार्य भी करना चाहिए। इससे कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से पर्याप्त वेतन समय पर मिल सके।

आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत कुमार ने अपने वर्चुवल संबोधन में खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं के बारे में बताया तथा पीएमईजीपी कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की। राज्य निदेशक डॉ. राहुल मिश्र ने आयोग की अन्य योजनाओं जैसे पीएमईजीपी, स्फूर्ति तथा ग्रामोद्योग विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। समारोह के अंत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहायक निदेशक बालेश्वर प्रसाद, डीसी सिघल, सुनील कुमार सक्सेना ने लाभार्थियों एवं आगुन्तकों का आभार प्रकट किया।

सब जगह हो नारी का सम्मान

हिलव्यू समाचार

जयपुर। महात्मा गांधी अस्पताल में इंडिया एज्यूकेशन ट्रस्ट की उपाध्यक्ष मीना स्वर्णकार ने कहा कि जहां नारी का सम्मान होता, वहां देवता निवास करते हैं। समाज में नारी का योगदान बराबर का है। घर हो, संस्थान हो सभी जगह नारी का सम्मान होना चाहिए। समारोह का आरंभ श्रीमती स्वर्णकार, डॉ. एमएल स्वर्णकार, डॉ विकास चंद्र स्वर्णकार द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा पर दीप प्रज्जवलन से हुआ। समारोह के दौरान अस्पताल की महिला डॉक्टर्स, नर्सेज तथा प्रशासनिक कर्मियों द्वारा मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई।

डीयू लिट फेस्ट: दीया कुमारी ने गायत्री देवी के संस्मरण पर चर्चा की

देश में बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने में अग्रणी थीं गायत्री देवी

हिलव्यू समाचार

जयपुर। 'गायत्री देवी न केवल मेरे लिए, बल्कि देश और विश्व भर में कई लोगों के लिए आदर्श थीं। व्यापक रूप से अपने आकर्षण और सुंदरता के लिए जानी जाने वाली एक खूबसूरत इंसान भी थीं।' ये विचार राजसमंद की सांसद दीया कुमारी ने डीयू लिट फेस्ट में रखे। उन्होंने कहा कि वे लड़कियों की शिक्षा के प्रति जुनूनी थीं और उन्होंने 1940 के दशक में स्कूलों और खेल संस्थानों की शुरुआत की। दीया कुमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल में थीं। उन्होंने स्वर्गीय गायत्री देवी के संस्मरण 'ए प्रिंसेस रिमेम्बर्स' पर जयपुर की लेखिका धर्मेंद्र कंवर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वह अपने समय से बहुत आगे थीं। एक महिला जिसने घोड़ों की सवारी की, बैडमिंटन और टेनिस खेलीं, गोल्फ क्लब और टेनिस क्लब शुरू किया और लड़कियों और महिलाओं के जीवन में बदलाव का नेतृत्व किया।

पूर्व राजमाता से मिली प्रेरणा

दीया कुमारी ने महाराजा सवाई मान सिंह सैकंड संग्रहालय को दुनिया के प्रमुख महल-संग्रहालयों में से एक बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजमाता से प्रेरित होकर उन्होंने प्रिंसेस दीया कुमारी फाउंडेशन (पीडीकेएफ) स्थापित किया था। महिलाओं को समाज में अपना सही स्थान हासिल करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। पीडीकेएफ उनकी तरह ही ग्रामीण और शहरी महिलाओं और लड़कियों के जीवन-कौशल को बढ़ा रहा है और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित कर रहा है।

महिलाओं की स्थिति हुई बेहतर

सांसद ने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं की स्थिति कई मायनों में बेहतर हुई है। महिला-केंद्रित और महिलाओं के नेतृत्व में विकास में बदलाव आया है। हालांकि, राजनीति एक पुरुष प्रधान क्षेत्र रहा है। आज के समय में लोकसभा में केवल 82 महिला सांसद हैं। महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने के लिए एक मजबूत समर्थन प्रणाली की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन सभी महिलाओं के लिए एक उदाहरण पेश किया है।

एक नज़र

झूलेलाल जन्मोत्सव का शुभारंभ

जयपुर। गणेश पूजन के साथ चेटीचंड सिन्धी मेला समिति जयपुर ग्रेटर की ओर से भगवान झूलेलाल जन्मोत्सव के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। सनातनी सिंधी समाज ने अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव को धर्म जागरण महोत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया। मुख्य संयोजक जयप्रकाश बुलचंदानी ने बताया कि सिंधी समाज बंधुओं ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर चेटीचंड सिन्धी मेला समिति,जयपुर ग्रेटर द्वारा प्रथम पूज्य गणेशजी का पूजन कर विधिवत न्यौता दिया। इसके बाद वाहनों से मालवीय नगर सेक्टर-4 स्थित श्री अंबे देवी धर्मशाला पहुंचे और यहां भगवान झूलेलाल जी का पूजन किया। कार्यक्रम के बाद कार्यकारिणी घोषित की गई और सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई।

ताऊ शेखावाटी सेठ शुभकरण पोद्दार साहित्य सम्मान-2023 से सम्मानित

जयपुर। बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट, झुंझुनूं की ओर से मंगलवार को सवाई माधोपुर के महाकवि ताऊ शेखावाटी को सांस्कृतिक मंडल सीकर द्वारा अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन के पिछले 37 वर्षों से लगातार संचालन और संयोजक करने पर सम्मानित किया गया। सीकर के दशहरा मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में ताऊ शेखावाटी को सेठ शुभकरण पोद्दार साहित्य सम्मान-2023 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाकवि ताऊ शेखावाटी को शॉल ओढ़ाकर और 51 हजार रुपए की राशि भेंट की गई। कवि ताऊ शेखावाटी के बताया कि पुरस्कार स्वरूप मिली राशि को वे हनुमान चरित के प्रकाशन पर खर्च करेंगे।

'हमारा सनातन' अभियान का आगाज

जयपुर। सांगानेर क्षेत्र में 'हमारा सनातन-विराट सनातन' अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत अभियान के संचालक शंकर लाल शर्मा ने बताया कि अभियान के जरिए सप्ताह में एक दिन अपने बच्चों, मित्रों और परिवारजनों के साथ मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

कविता

ऋतुराज

स्वागत है रितुराज तुम्हारा
ओढ़ धारा ने पीली चादर
और हरित कालीन बिछाया
मन मयूर पंखों को खोलें
करते नृत्य निराला...स्वागत है..
कहीं कोकिला की सप्तम में
और पंछियों की कलरव में
झरने की नित्य मधु कल कल में
फूलों पर मंडराती भंवरे भी
गुंजाते मृदुगान तुम्हारा.. स्वागत है..
आखेटक मन मुग्ध धरा पर
झरते अश्रु अवरुद्ध कंठ से
कहीं मृत्यु भय छोड़ मिरग भी.
आकर्षित वशीभूत विचरते
और करते नितगान तुम्हारा..स्वागत है
मन कुमुदिनी सा खिला सरोवर
देख शीतल मयंक मृदु छाया
जब तारों की चादर ओढ़े
आई नवल बिभूति बाला
दादुर संग जजीरे ने भी
छेड़ा राग प्यारा. स्वागत है..

स्मिता शुक्ला
चित्रकार एवं कवयित्री

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, एवं मुद्रक शालिनी श्रीवास्तव के लिए अम्बर ऑफसेट प्राइवेट लिमिटेड, डी.एल. टॉवर, 3-ए, विद्याश्रम संस्थानिक क्षेत्र, जेएलएन मार्ग, जयपुर में मुद्रित एवं प्लॉट नंबर C-2,अर्शिया रेजिडेंसी, फ्लैट नंबर 201,आदर्श नगर,राजा पार्क जयपुर-302004 (राजस्थान) से प्रकाशित।
संपादक : शालिनी श्रीवास्तव **सह-संपादक:** हरीश श्रीवास्तव, छबड़ा बारां **सह-संपादक :** कुलदीप गुप्ता, जयपुर मो.: 9460678701, 7976561127 (21 जून 2014 से निरन्तर प्रकाशित) hillviewsamachar@gmail.com (राजस्थान सरकार से विज्ञापन हेतु स्वीकृत)